facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 19 जनवरी 2026 ● वर्ष 7 ● अंक 27 ● मूल्यः 5 रुपए

"पाकिस्तान अपने बनने का असली...

दुबई में प्रेम और भक्ति का महासंगम

गुरुदेव–गुरुमां की वैवाहिक वर्षगांठ पर प्रेम दिवस बना अविस्मरणीय

@ भारतश्री ब्यूरो

विदेशी धरती पर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की अनुपम झलक उस समय देखने को मिली जब दुबई में प्रेम, भक्ति और उल्लास से भरा प्रेम दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस पावन अवसर पर दुबई वासियों ने जगतगुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी और गुरुमां की वैवाहिक वर्षगांठ को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और यह आयोजन प्रेम व भक्ति के अद्भुत संगम में बदल गया।

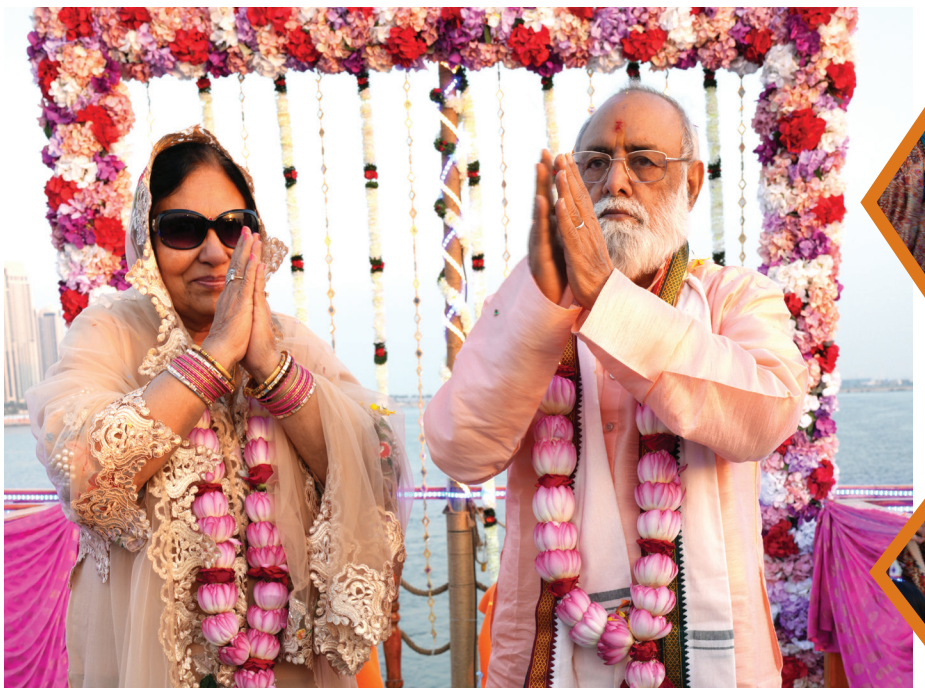

भजन और सत्संग से गूंज उठा वातावरण

कार्यक्रम की शुरुआत भजन और सत्संग से हुई। जैसे ही भक्ति संगीत की गूंज सभागार में फैली, हर हृदय उससे जुड़ता चला गया। श्रद्धालु केवल दर्शक बनकर नहीं बैठे बल्कि भक्ति में डूबकर नाचे भी और गाए भी। भजनों की पंक्तियों में प्रेम, समर्पण और मानवता का संदेश साफ झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दुबई की धरती कुछ समय के लिए अध्यात्म में पूरी तरह डूब गई हो।

गुरुदेव–गुरुमां के सान्निध्य में भावनात्मक क्षण

महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी और गुरुमां के सान्निध्य ने प्रेम दिवस को एक साधारण उत्सव से कहीं आगे ले जाकर आत्मिक अनुभव में बदल दिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि यह केवल एक समारोह नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला अवसर है। यहां प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का आधार बताया गया। हर चेहरा संतोष और शांति से भरा नजर आया।

दुबई की संगत ने रचा भव्य आयोजन

दुबई की संगत ने आयोजन को भव्य और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सजावट से लेकर व्यवस्थाओं तक हर पहलू में श्रद्धा और समर्पण साफ दिखाई दिया। फूलों से सजा मंच, भक्ति संगीत और अनुशासित व्यवस्था ने पूरे माहौल को विवाह समारोह जैसा बना दिया। दुबई में रहने वाले भारतीयों के साथ-साथ विभिन्न देशों से आए श्रद्धालु भी इस अवसर के साक्षी बने।

ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतू खुसबू जी का भावुक संदेश

इस मौके पर ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतू खुसबू जी ने दुबई की संगत की दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि दुबई वाले वास्तव में बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें सालों से गुरुदेव के विशेष दिन को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।उन्होंने कहा कि आप लोग जिस प्रेम और समर्पण से गुरुदेव और गुरुमां की वर्षगांठ मनाते हैं, वह देखने योग्य होता है। आप लोग गुरुमा जी को दुल्हन की तरह सजाते हैं, गुरुदेव को भी उसी प्रेम से तैयार करते हैं और पूरा शादी वाला माहौल बना देते हैं। आप लोग सच में धन्य हैं।

संगत के लिए प्रेरणा बना संदेश

ब्रह्मस्वरूपिणी जी के शब्दों ने वहां मौजूद हर श्रद्धालु को भावुक कर दिया। यह केवल प्रशंसा नहीं बल्कि दुबई की संगत और गुरुदेव के बीच गहरे आत्मिक रिश्ते की अभिव्यक्ति थी। सभागार तालियों की गूंज से भर उठा।

जतिन शर्मा वशिष्ठ जी ने जताई श्रद्धा

कार्यक्रम में जतिन शर्मा वशिष्ठ जी ने गुरुदेव को नमन करते हुए कहा कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी पर अनवरत बना रहे। उन्होंने कहा कि संगत इसी तरह उत्साह और श्रद्धा के साथ हर वर्ष गुरुदेव की वर्षगांठ मनाती रहे। उनका कहना था कि गुरुदेव का सान्निध्य जीवन को सकारात्मक दिशा देता है और ऐसे आयोजन नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

दुबई क्रूज पर मनाई गई वर्षगांठ

इस अवसर पर जगतगुरु जी एवं पूज्य माताजी ने दुबई की संगत के साथ दुबई क्रूज़ में अपनी वैवाहिक वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। लहरों के बीच यह आयोजन और भी भावनात्मक हो गया। क्रूज़ पर भक्ति संगीत, सामूहिक प्रार्थना और प्रेम भरे क्षणों ने सभी को एक सूत्र में बांध दिया। यह दृश्य हर उपस्थित व्यक्ति के लिए हमेशा यादों में रहने वाला बन गया।

कई गणमान्य अतिथि बने साक्षी

इस भव्य समारोह में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। श्री पी एन अग्रवाल जी, पूज्य स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अतिथियों ने इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से प्रेरणादायक बताया।

विदेश में भी जीवित भारतीय संस्कृति

दुबई में बसे श्रद्धालुओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़े रखते हैं। गुरुदेव और गुरुमां का सान्निध्य उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। प्रेम दिवस के इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम सेवा, समर्पण और सद्भाव में प्रकट होता है।कुल मिलाकर दुबई में मनाया गया यह प्रेम दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने प्रेम, भक्ति और मानवीय मूल्यों को नई मजबूती दी। यह आयोजन लंबे समय तक श्रद्धालुओं की स्मृतियों में जीवित रहेगा और प्रेम के वास्तविक अर्थ को स्थापित करता रहेगा।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

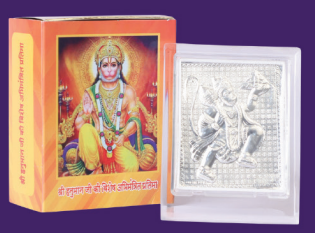

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का महासैलाब

प्रशासन के अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालु, एक दिन में 4.52 करोड़ ने लगाई गंगा—संगम में डुबकी

@ शोभित यादव

माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर रविवार को प्रयागराज पूरी तरह आस्था के सागर में डूबा नजर आया। तड़के सुबह से लेकर देर शाम तक गंगा, यमुना और संगम तट पर श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी रही। हालात ऐसे बने कि प्रशासन द्वारा लगाए गए अनुमान भी पीछे छूट गए। जहां मौनी अमावस्या पर करीब तीन करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, वहीं फाइनल आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र स्नान किया।प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से देर शाम जारी किए गए आंकड़ों ने यह साफ कर दिया कि इस बार मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। अकेले शाम चार बजे तक 3 करोड़ 82 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे, जबकि दिन ढलते-ढलते यह संख्या और बढ़ गई।

रात से ही संगम की ओर बढ़ने लगे श्रद्धालु

मेला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं का संगम और गंगा घाटों की ओर पहुंचना शुरू हो गया था। आधी रात के बाद ही घाटों पर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। जैसे-जैसे सुबह हुई, भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता चला गया।संगम क्षेत्र, अरैल घाट, दारागंज, झूंसी, किला घाट और अन्य प्रमुख स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी रही। श्रद्धालु परिवारों के साथ पहुंचे थे। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आए।

हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा

मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संगम और मेला क्षेत्र में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं और साधु-संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जैसे ही आसमान से फूल बरसने लगे, संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। इस दृश्य ने माहौल को और भी भावनात्मक और भक्तिमय बना दिया।श्रद्धालुओं का कहना था कि पुष्प वर्षा ने उनके स्नान को और अधिक पुण्यकारी बना दिया। कई लोगों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया।

भीड़ ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

माघ मेले में इससे पहले भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन मौनी अमावस्या पर उमड़ी भीड़ ने सभी पुराने आंकड़े पार कर दिए। प्रशासन के मुताबिक, इससे पहले मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। वहीं एकादशी के अवसर पर करीब 85 लाख लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई थी।इन आंकड़ों की तुलना में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा रही। मेला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या माघ मेले के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है।

संगम नोज पर विवाद, शंकराचार्य को रोका गया

मौनी अमावस्या के दिन सुबह उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भारी संख्या में समर्थकों के साथ संगम जाने से पुलिस ने रोक दिया। यह घटना संगम नोज क्षेत्र की बताई जा रही है।मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शंकराचार्य अपने लगभग 200 से 250 समर्थकों के साथ बिना किसी पूर्व अनुमति के पुल नंबर दो के बैरियर को तोड़ते हुए स्नान घाट की ओर बढ़ने लगे। भीड़ अत्यधिक होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य को पहले ही अवगत कराया गया था कि संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ है। इसके बावजूद वह नहीं माने और समर्थकों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया।नीरज पांडेय के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका गया, जिसके बाद शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस प्रशासन सभी साधु-संतों का सम्मान करता है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। भीड़ नियंत्रण और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए नियमों का पालन जरूरी है।

प्रशासन के सामने रही बड़ी चुनौती

इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा। इसके बावजूद प्रशासन ने ट्रैफिक, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पहले से की गई तैयारियों के दम पर हालात को काबू में रखा।मेला क्षेत्र में लगातार पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात रहे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भीड़ पर नजर रखी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रहा।

श्रद्धालुओं के लिए किए गए विशेष इंतजाम

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखाने और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मेला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए। मेले के प्रमुख मार्गों और खंभों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, ताकि रात के समय भी रास्ते साफ दिखाई दें।इसके अलावा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती की गई, जो श्रद्धालुओं को सही दिशा दिखाने में मदद कर रहे थे। लाउडस्पीकर के जरिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, ताकि लोग अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

घाटों पर दिखा अनुशासन

इतनी भारी भीड़ के बावजूद घाटों पर श्रद्धालुओं में अनुशासन देखने को मिला। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी लगातार लोगों को स्नान के बाद घाट खाली करने की अपील करते रहे, ताकि अन्य श्रद्धालु भी सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकें।स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी मेडिकल कैंप लगाए गए थे। मामूली चोट, थकान या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए डॉक्टर और एंबुलेंस मौके पर मौजूद रहीं।

श्रद्धालुओं ने जताया संतोष

स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। उनका कहना था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद रास्तों, सुरक्षा और सुविधाओं में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ संगम में स्नान करते देखा।

माघ मेले की गरिमा और बढ़ी

मौनी अमावस्या पर उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ ने माघ मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ा दिया। साधु-संतों के अखाड़े, कल्पवासी, श्रद्धालु और पर्यटक सभी ने मिलकर प्रयागराज को आस्था की राजधानी बना दिया।प्रशासन का कहना है कि आने वाले प्रमुख स्नान पर्वों को देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है।कुल मिलाकर मौनी अमावस्या का यह दिन प्रयागराज के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और प्रशासन की व्यवस्थाएं एक साथ नजर आईं। गंगा और संगम में डुबकी लगाकर लौटते लोगों के चेहरों पर संतोष और श्रद्धा साफ झलक रही थी।माघ मेले में मौनी अमावस्या ने यह साबित कर दिया कि आस्था जब उमड़ती है, तो वह हर अनुमान को पीछे छोड़ देती है।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026: महायुति की मजबूत पकड़ और राजनीतिक बदलाव की दिशा

चुनाव परिणामों का पहला नजरिया

महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को हुए 29 नगर निगमों के चुनावों के नतीजे आज 16 जनवरी को आए हैं, और ये नतीजे राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, ने ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल की है। कुल 29 नगर निगमों में से महायुति 19 पर आगे है, जबकि कांग्रेस ने 5 पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मुंबई की ब्रिहनमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में 227 वार्डों में से महायुति ने 118 पर लीड ली है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) गठबंधन को सिर्फ 83 पर संतोष करना पड़ा है। पूरे राज्य में भाजपा अकेले 1,088 सीटों पर आगे है, जो दिखाता है कि शहरी इलाकों में उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो गई है। लातूर नगर निगम में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, जबकि भाजपा को 22 मिलीं। अन्य जगहों जैसे पुणे, नागपुर, ठाणे और नवी मुंबई में भी महायुति का दबदबा रहा। ये चुनाव कोविड और कानूनी मुद्दों की वजह से देरी से हुए थे, और वोटरों ने सड़क, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। एग्जिट पोल ने पहले ही महायुति की जीत की भविष्यवाणी की थी, और नतीजे उससे मेल खाते हैं। ये परिणाम दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में अब महायुति का बोलबाला है, लेकिन विपक्ष के लिए भी कुछ उम्मीद की किरणें हैं, जैसे लातूर में कांग्रेस की जीत। कुल मिलाकर, ये चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद की स्थिति को मजबूत करते हैं।

मुंबई बीएमसी: सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र और उसके नतीजे

मुंबई की बीएमसी चुनाव राज्य के सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये भारत की सबसे अमीर नगर निकाय है और यहां की राजनीति पूरे देश पर असर डालती है। 227 वार्डों में महायुति ने 116 से ज्यादा पर जीत दर्ज की, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। ठाकरे भाइयों ने 20 साल बाद हाथ मिलाया था, ताकि बाल ठाकरे की विरासत को बचाया जा सके, लेकिन उन्हें सिर्फ 85 के आसपास वार्ड मिले। एमएनएस को 9 और कांग्रेस को 10 पर लीड मिली, जो दिखाता है कि विपक्ष बिखरा हुआ था। मुंबई के मराठी इलाकों जैसे दादर, परेल और वर्ली में ठाकरों को उम्मीद थी, लेकिन वहां भी महायुति ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये नतीजे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका हैं, क्योंकि शिवसेना ने 30 साल से बीएमसी पर कब्जा किया हुआ था। अब महायुति मुंबई के मेयर पद पर काबिज होगी, जो शहर की बुनियादी समस्याओं जैसे सड़कें, पानी और ट्रैफिक को संभालने में अपनी नीतियां लागू कर सकेगी। हालांकि, कुछ जगहों पर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अच्छा किया, जैसे लातूर में जहां कांग्रेस ने 43 सीटें जीतीं। ये दिखाता है कि स्थानीय मुद्दे अभी भी वोटरों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा हावी नहीं रह सकतीं। कुल मिलाकर, बीएमसी के नतीजे महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में भाजपा की बढ़ती ताकत को रेखांकित करते हैं, लेकिन ये ये भी बताते हैं कि गठबंधन कितने अस्थिर हो सकते हैं। भविष्य में ये परिणाम राज्य की अन्य चुनावों पर असर डालेंगे, क्योंकि मुंबई की जीत से महायुति का मनोबल ऊंचा होगा।

अन्य नगर निगमों में पार्टियों का प्रदर्शन

राज्य के अन्य 28 नगर निगमों में भी नतीजे दिलचस्प रहे, जहां महायुति ने अपनी पकड़ मजबूत की। पुणे में भाजपा ने पवार परिवार के गढ़ को झटका दिया, और वहां महायुति आगे रही। पिंपरी-चिंचवड़, नासिक और ठाणे में भी भाजपा और उसके सहयोगियों ने अच्छा किया, जहां भाजपा अकेले 27 से ज्यादा सीटों पर आगे है। नागपुर में संघ का प्रभाव दिखा, और महायुति ने आसानी से जीत हासिल की। हालांकि, लातूर में कांग्रेस ने सबको हैरान कर दिया, जहां उसने 43 सीटें जीतकर भाजपा को 22 पर रोक दिया। कोल्हापुर में भी कांग्रेस आगे रही, जो दिखाता है कि ग्रामीण-शहरी मिश्रित इलाकों में विपक्ष अभी भी मजबूत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को ज्यादा फायदा नहीं मिला, और अजित पवार का गुट महायुति के साथ मिलकर कुछ सीटें जीता। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 4 सीटें लातूर में जीतीं, जो अल्पसंख्यक और दलित वोटरों की ताकत दिखाती है। कुल मिलाकर, भाजपा ने पूरे राज्य में 866 वार्डों पर लीड ली, जबकि शिवसेना (शिंदे) 216 पर आगे रही। ये नतीजे बताते हैं कि 2024 विधानसभा चुनावों के बाद महायुति की एकजुटता काम आई, लेकिन विपक्ष के लिए लातूर जैसी जीतें उम्मीद जगाती हैं। स्थानीय मुद्दों जैसे विवादास्पद बयान और बुनियादी सुविधाओं ने वोटरों को प्रभावित किया। ये चुनाव दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब ज्यादा विभाजित है, जहां राष्ट्रीय मुद्दे कम और स्थानीय समस्याएं ज्यादा मायने रखती हैं। भविष्य में ये परिणाम गठबंधनों को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि पार्टियां अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करेंगी।

भविष्य के चुनावों पर पड़ने वाला असर

ये नगर निगम चुनावों के नतीजे महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति पर गहरा असर डालेंगे, खासकर 2029 के विधानसभा चुनावों पर। महायुति की जीत से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का कद बढ़ेगा, और ये शहरी इलाकों में भाजपा की ताकत को मजबूत करेगी। मुंबई जैसे बड़े शहरों पर कब्जा होने से महायुति को फंडिंग और संसाधनों का फायदा मिलेगा, जो अगले चुनावों में प्रचार के लिए काम आएगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए ये झटका है, क्योंकि ठाकरों का पुनर्मिलन काम नहीं आया, और ये उनकी विरासत पर सवाल उठाता है। एमएनएस को कम सीटें मिलने से राज ठाकरे की भूमिका कम हो सकती है। हालांकि, कांग्रेस की लातूर और कोल्हापुर जैसी जीतें दिखाती हैं कि विपक्ष अभी खत्म नहीं हुआ, और वो मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर वापसी कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये नतीजे 2029 के लिए संकेत हैं, जहां शहरी वोटर निर्णायक होंगे। महायुति की जीत से केंद्र सरकार का समर्थन बढ़ेगा, और ये राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की छवि मजबूत करेगी। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो, तो वो इन नतीजों से सीख लेकर मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर, ये चुनाव बताते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी है, जहां स्थानीय गठबंधन और मुद्दे बड़े फैक्टर होंगे। ये परिणाम सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या महायुति की ये जीत स्थायी है, या विपक्ष नई रणनीति से वापसी करेगा।

संतुलित नजरिया और आगे की चुनौतियां

इन चुनावों को देखते हुए, एक संतुलित नजरिया ये है कि महायुति की जीत विकास और स्थिरता की तरफ इशारा करती है, लेकिन विपक्ष की कुछ सफलताएं लोकतंत्र की मजबूती दिखाती हैं। भाजपा की बढ़ती ताकत शहरी विकास पर फोकस करेगी, लेकिन ठाकरों जैसे स्थानीय नेताओं की हार से मराठी अस्मिता का मुद्दा उठ सकता है। कांग्रेस की जीत बताती है कि स्थानीय नेता और मुद्दे अभी भी मायने रखते हैं, जैसे लातूर में विवादास्पद बयानों का असर। ये नतीजे सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बड़े गठबंधन हमेशा कामयाब होंगे, या छोटे मुद्दे उन्हें चुनौती देंगे। भविष्य में, पार्टियां वोटरों की उम्मीदों जैसे बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देंगी, क्योंकि चुनावों में ये ही निर्णायक रहे। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र की राजनीति अब ज्यादा गतिशील है, जहां कोई भी पार्टी हमेशा हावी नहीं रह सकती। ये चुनाव एक विचार देता है कि लोकतंत्र में बदलाव संभव है, और पार्टियां इससे सीख लेंगी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

बांग्लादेश की सेना में दरार: पाकिस्तान के छिपे हाथ और तख्तापलट की आशंका

सेना की फूट का असली कारण क्या है?

बांग्लादेश में हाल के महीनों में राजनीतिक उथल-पुथल ने देश की सेना को दो हिस्सों में बांट दिया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अंतरिम सरकार चल रही है, लेकिन सेना के अंदर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। सेना प्रमुख वाकर-उज-जमान ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए हैं, जिससे कुछ अधिकारी नाराज हैं। ये अधिकारी मानते हैं कि ये कदम लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हाल में एक प्रमुख छात्र नेता शरीफ ओसमान हादी की हत्या ने हिंसा को और भड़का दिया है। हादी भारत विरोधी थे और अवामी लीग को भारत समर्थक बताते थे। उनकी मौत के बाद दंगे भड़के, जिसमें मीडिया हाउस जलाए गए और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। सेना के एक हिस्से का मानना है कि ये हिंसा पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों की साजिश है, जो पुरानी दुश्मनी को भुनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े कुछ अधिकारी कथित रूप से इस फूट को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 में हादी की हत्या ने भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिससे चुनाव से पहले तनाव बढ़ा है। 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनावों में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी जैसे दल फायदे में हैं। सेना के दूसरे हिस्से का कहना है कि ये फूट देश को अस्थिर कर रही है, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी, सड़कों पर प्रदर्शन और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो देश की एकता पर सवाल उठा रही हैं। क्या ये मतभेद सिर्फ राजनीतिक हैं या कुछ गहरा है? ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि इतिहास बताता है कि बांग्लादेश में सेना की भूमिका हमेशा अहम रही है।

पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों की भूमिका

बांग्लादेश की सेना में पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों का होना कोई नई बात नहीं है। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से कुछ अधिकारी पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते रखते हैं। हाल की हिंसा के पीछे इन्हीं अधिकारियों का हाथ बताया जा रहा है। छात्र नेता हादी की हत्या के बाद दंगे भड़के, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई का नाम आया है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आईएसआई बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के लिए काम कर रही है, ताकि भारत पर दबाव बने। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान जैसे अधिकारी कथित रूप से इस्लामी कट्टरवादियों से जुड़े हैं और आईएसआई से समर्थन ले रहे हैं। ये अधिकारी सेना प्रमुख के फैसलों से असहमत हैं, खासकर शेख हसीना को भारत में शरण देने पर। एक्स (ट्विटर) पर कई पोस्ट्स में ये दावा किया गया है कि सेना की 9वीं इन्फैंट्री डिवीजन ढाका में तैनात हो गई है, जो फूट का संकेत है। एक पोस्ट में कहा गया कि कट्टर छात्र समूह सेना प्रमुख से नाराज हैं, क्योंकि वो अवामी लीग को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक अधिकारी हिंसा को हवा दे रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यकों पर हमले और मीडिया पर अटैक। ये सब चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगती है। लेकिन दूसरी तरफ, सेना का बड़ा हिस्सा देश की स्थिरता चाहता है और भारत से अच्छे रिश्ते रखना जरूरी मानता है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की लोकप्रियता घटी है, लेकिन वो सेना के साथ मिलकर स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान समर्थक ताकतें देश को 1971 जैसी स्थिति में धकेल देंगी? ये चिंता बढ़ रही है, क्योंकि हिंसा थम नहीं रही। बैलेंस्ड नजरिए से देखें तो दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, ताकि फूट न बढ़े।

छात्र नेताओं का तख्तापलट का आरोप

छात्र नेता बांग्लादेश की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन में छात्रों ने शेख हसीना की सरकार गिराई थी। अब वो सेना पर तख्तापलट की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। छात्र नेता कहते हैं कि पाकिस्तान समर्थक अधिकारी अंतरिम सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस्लामी कट्टरवादी सत्ता में आएं। हादी की हत्या के बाद छात्रों ने कहा कि ये साजिश का हिस्सा है, जिसमें आईएसआई शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में छात्र पार्टी के एक नेता ने कहा कि सेना प्रमुख भारत समर्थक हैं, इसलिए कट्टर समूह उनसे नाराज हैं। छात्रों का मानना है कि सेना की फूट चुनाव को प्रभावित करेगी, और अगर तख्तापलट हुआ तो देश में अराजकता फैलेगी। लेकिन छात्र पार्टी की लोकप्रियता भी घटी है, इसलिए उन्होंने जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन किया है। जमात चुनाव में मजबूत है, लेकिन छात्र नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर साजिश कामयाब हुई तो सिविल वॉर हो सकता है। अंतरिम सरकार पर दबाव है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन हिंसा बढ़ रही है। छात्रों का कहना है कि मीडिया हाउस जलाना और अल्पसंख्यकों पर हमले साजिश का हिस्सा हैं, ताकि डर फैले। दूसरी तरफ, सेना का कहना है कि वो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है। क्या छात्रों के आरोप सही हैं? इतिहास देखें तो 1971 में भी छात्रों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये है कि क्या वो फिर से देश को एकजुट कर पाएंगे या फूट बढ़ेगी। बैलेंस्ड तरीके से देखें तो छात्रों की बात में दम है, लेकिन सेना को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये स्थिति विचार करने लायक है, क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं।

सिविल वॉर का खतरा कितना बड़ा?

बांग्लादेश में सिविल वॉर की आशंका बढ़ रही है, लेकिन क्या ये वाकई होगा? सेना की फूट, हिंसा और राजनीतिक दलों के बीच टकराव देश को अस्थिर कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में हादी की हत्या के बाद दंगे भड़के, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। सेना प्रमुख ने कहा कि आपसी झगड़ों से देश खतरे में है। पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों की वजह से हिंसा बढ़ी है, जो आईएसआई से जुड़े हैं। छात्र नेता तख्तापलट की साजिश बता रहे हैं, लेकिन सेना इसे नकार रही है। चुनाव से पहले बीएनपी की वापसी हुई है, जब तारिक रहमान लंदन से लौटे। लेकिन जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के बीच झड़पें हो रही हैं। अगर सेना के दो हिस्से आमने-सामने आए तो सिविल वॉर हो सकता है, जैसे 1971 में हुआ था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जैसे भारत और अमेरिका, दबाव बना रहे हैं कि शांति बनी रहे। अंतरिम सरकार अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम रही है, जिससे गारमेंट इंडस्ट्री में हड़तालें हो रही हैं। क्या सिविल वॉर होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बातचीत हुई तो बचाव संभव है। लेकिन हिंसा जारी रही तो खतरा बड़ा है। बैलेंस्ड नजरिए से, दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि देश की एकता जरूरी है। इतिहास से सीख लें, क्योंकि 1971 की जंग ने देश को आजादी दी, लेकिन अब फूट देश को पीछे धकेल सकती है। विचार करने का समय है कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश से ऊपर है?

भविष्य की राह और संभावित हल

बांग्लादेश का भविष्य अब चुनावों पर टिका है, लेकिन सेना की फूट और हिंसा चुनौती बनी हुई है। पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों को अलग करना जरूरी है, ताकि साजिश रुके। छात्र नेता चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अंतरिम सरकार को सभी दलों से बात करनी चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों। भारत से रिश्ते सुधारना भी अहम है, क्योंकि आर्थिक मदद जरूरी है। अगर सिविल वॉर टला तो देश विकास कर सकता है। लेकिन अगर फूट बढ़ी तो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बर्बाद होंगे। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सेना को राजनीति से दूर रखें और लोकतंत्र मजबूत करें। छात्रों की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, न कि हिंसक। पाकिस्तान की दखलंदाजी रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद लें। बैलेंस्ड तरीके से देखें तो हर पक्ष की जिम्मेदारी है। क्या देश एकजुट हो पाएगा? ये समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि शांति जीतेगी।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 19 जनवरी 2026 , विक्रम संवत 2080

इंसानियत पर कानून का हस्तक्षेप क्यों?

उड़ीसा प्रदेश के भद्रक जिले में एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची किसी दूसरे परिवार को दे दी और उस परिवार ने उस महिला को 35000 रुपए दिए। मेरे विचार से इसमें कौन सा अपराध हो गया। बच्ची को देने वाला सहमत बच्ची को लेने वाला सहमत। पेशेवर मानवाधिकार वाले असहमत हो गए। अच्छा होता कि मानव अधिकार वादी उसको 100000 में ले लेते कौन रोक रहा था। सरकार ने उस महिला पर अपराध कायम कर दिया उस महिला ने उस बच्ची को मारा नहीं जिंदा दिया मैं अभी तक नहीं समझ सका कि यह मानवाधिकार वादी या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। अभी तक मैं सुनता था कि सिर्फ छोटे बच्चे ही लोग पैसे देकर गोद लेते हैं अब यह सुन रहा हूं कि छोटी-छोटी बच्चियों भी अगर इतना महत्व पा रहे हैं इसमें किसी को जलन क्यों होनी चाहिए । उस महिला ने आर्थिक संकट के कारण बच्ची दी अथवा किसी अन्य समस्या के कारण यह तो वही बता सकती है लेकिन मेरे विचार से इसमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ है यदि कानून से गलत है तो कानून गलत है कानून को बदलना चाहिए ना कि वह महिला जिसने अपनी बच्ची को दिया है। इस पूरे लेनदेन में किसी प्रकार का अपराध मानना पूरी तरह गलत है।

ज्ञानेंद्र आर्य

ग्रीनलैंड और शक्ति की राजनीति

@ **अनुराग पाठक**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड को लेकर दोबारा सख्त रुख दिखाना केवल एक बयान भर नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति और आने वाले समय की भू-रणनीतिक तस्वीर की ओर संकेत करता है। ट्रम्प ने जिस स्पष्टता और आक्रामकता के साथ यह कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, उससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका इस क्षेत्र को अब सिर्फ एक दूरस्थ द्वीप नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम चौकी के रूप में देख रहा है।

ग्रीनलैंड का महत्व अचानक नहीं बढ़ा है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका यहां अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। थुले एयर बेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज भी मिसाइल चेतावनी और निगरानी के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसने अमेरिका और NATO देशों की चिंता को और गहरा कर दिया है। ट्रम्प का बयान इसी चिंता की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।ट्रम्प यह मानते हैं कि ताकत के जरिए ही शांति कायम की जा सकती है। यह सोच उनकी विदेश नीति का मूल आधार रही है। ग्रीनलैंड को लेकर उनका रुख भी इसी सोच का विस्तार है। वह इसे केवल डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा एक रणनीतिक मोर्चा मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने NATO प्रमुख से बातचीत, दावोस में बैठक और सैन्य गतिविधियों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देगा।

हालांकि इस पूरे मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि क्या शक्ति प्रदर्शन ही हर समस्या का समाधान है। NATO जैसे संगठन की बुनियाद सामूहिक सुरक्षा और आपसी सहमति पर टिकी है। एक NATO सदस्य देश द्वारा दूसरे सदस्य देश के क्षेत्र को लेकर आक्रामक बयान देना संगठन की मूल भावना के विपरीत माना जा सकता है। यही वजह है कि ट्रम्प द्वारा NATO चीफ के निजी संदेश को सार्वजनिक करना यूरोप के कई देशों को असहज कर गया है। कूटनीति में संवाद जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी उसकी मर्यादा भी होती है।डेनमार्क की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि यूरोपीय देश ग्रीनलैंड के सवाल को हल्के में नहीं ले रहे। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और सैन्य अभ्यास यह दिखाते हैं कि डेनमार्क अपनी संप्रभुता और जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क है। फ्रांस और अन्य NATO देशों का समर्थन यह संदेश देता है कि यूरोप इस मुद्दे पर एकजुट रहना चाहता है। यह एक राजनीतिक संकेत भी है कि ग्रीनलैंड केवल अमेरिका और डेनमार्क के बीच का मामला नहीं, बल्कि पूरे NATO की सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और भविष्य की वैश्विक व्यवस्था से भी जुड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे नई समुद्री व्यापारिक राहें खुल रही हैं, जो आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापार का स्वरूप बदल सकती हैं। इन रास्तों पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़त। इसके अलावा ग्रीनलैंड में मौजूद दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भविष्य की तकनीक और उद्योग के लिए बेहद अहम हैं। चीन पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, और अमेरिका इस निर्भरता को कम करना चाहता है।कानूनी दृष्टि से देखें तो ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना इतना आसान नहीं है। यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और वहां के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। किसी भी तरह का बदलाव जनमत संग्रह और डेनिश संसद की मंजूरी के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा NATO की संधियां भी किसी जबरन कब्जे या दबाव की इजाजत नहीं देतीं। ऐसे में ट्रम्प के बयान फिलहाल एक राजनीतिक दबाव और रणनीतिक संदेश के रूप में ही देखे जा रहे हैं, न कि किसी तात्कालिक कार्रवाई की भूमिका के रूप में।

यह पूरा विवाद दरअसल एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। दुनिया एक बार फिर शक्ति संतुलन के नए दौर में प्रवेश कर रही है। आर्कटिक अब केवल बर्फ और निर्जन इलाकों का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह भविष्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड इसी बदलाव का प्रतीक है।ट्रम्प का सख्त रुख यह दिखाता है कि अमेरिका इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस प्रतिस्पर्धा में कूटनीति, सहमति और अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी न हो। यदि शक्ति की राजनीति संतुलन से बाहर गई, तो यह टकराव और अस्थिरता को जन्म दे सकती है।

ग्रीनलैंड का सवाल इसलिए केवल एक द्वीप का सवाल नहीं है। यह आने वाले समय में यह तय करेगा कि वैश्विक राजनीति सहयोग और नियमों के आधार पर चलेगी या फिर खुली शक्ति प्रदर्शन की राह पर। अमेरिका, NATO और यूरोप के सामने यह एक परीक्षा की घड़ी है, जहां हर कदम दूरगामी असर डाल सकता है।

जुबानी तीर

“ मेरे साथ और मेरे शिष्यों के साथ जो व्यवहार हुआ, वह संत परंपरा के सम्मान के विरुद्ध है। हम व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ससम्मान संगम स्नान हमारा अधिकार है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ज्योतिषपीठ शंकराचार्य

“ मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ थी। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि थी। किसी संत या परंपरा का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था।

नीरज पांडेय, पुलिस अधीक्षक (माघ मेला)

“ माघ मेला देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए कुछ निर्णय लेने पड़े। पूरे मामले की तथ्यात्मक समीक्षा की जा रही है।

सौम्या अग्रवाल, मंडलायुक्त प्रयागराज

“ संतों के सम्मान की बात करने वाली सरकार में अगर साधु-संत खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो यह बेहद चिंताजनक है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

आंखों की सेहत और आयुर्वेद

आंख आने पर क्या करे?

आंख आना, जिसे आयुर्वेद में अभिष्यंद भी कहा जाता है, आंखों में सूजन, लालिमा, जलन तथा पानी या मवाद आने की स्थिति है। सामान्य भाषा में इसे आँख आना, आँख की गिल्टी, सूजन या Conjunctivitis भी कहा जाता है। यह समस्या मौसम परिवर्तन, संक्रमण, धूल, एलर्जी या शरीर में बढ़ते पित्त-दोष के कारण अधिक देखी जाती है।आयुर्वेद के अनुसार, आंखें पित्त का प्रमुख स्थान हैं। जब पित्त बढ़ता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो आंखें तुरंत प्रभावित होती हैं। लालिमा, जलन, दर्द और पानी आना, पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। वहीं, धूल-मिट्टी, संक्रमित वस्तुओं के संपर्क और गंदे हाथों से आंख रगड़ने पर संक्रमण फैल जाता है।इस लेख में हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आंख आने के कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, सावधानियाँ और आहार-विहार के सुझाव विस्तार से समझेंगे।

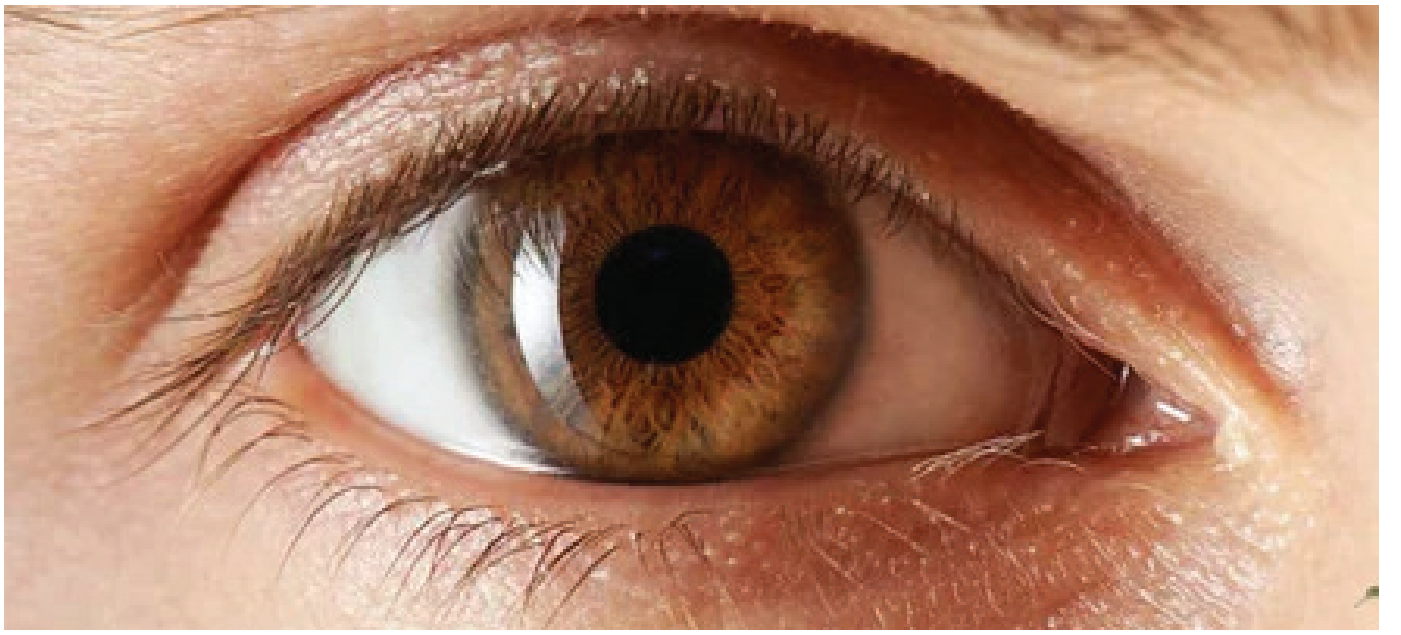

आंख आने के प्रमुख कारण

संक्रमण (Infection)

बैक्टीरिया या वायरस के कारण सबसे अधिक मामले सामने आते हैं, जो अत्यंत संक्रामक होते हैं।

धूल, धुआं और प्रदूषण

प्रदूषित वातावरण आंखों को चुभन और जलन देता है, जिससे सूजन हो जाती है।

पित्त का बढ़ना

मसालेदार भोजन, धूप, स्क्रीन टाइम, मानसिक तनाव—ये सभी पित्त बढ़ाते हैं।

एलर्जी

परागकण (Pollens), कॉस्मेटिक, केमिकल या मौसम परिवर्तन से शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया।

कमजोर प्रतिरोधक क्षमता

जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें यह समस्या जल्दी होती है।

आंख आने के लक्षण

आंखों में लालिमा

पानी या मवाद निकलना

पलक सूज जाना

आंख चिपक जाना

जलन या खुजली

धुंधला दिखना

तेज धूप में चुभन

आयुर्वेद में कहा गया है पित्तप्रधान नेत्ररोगो रक्तपित्त-प्रकोपजः अर्थात जब पित्त बढ़ता है, तब नेत्ररोग स्वाभाविक रूप से बढ़ता है।

आंख आने पर आयुर्वेदिक उपचार (घरेलू नुस्खे)

नीचे दिए गए उपाय सुरक्षित, सरल और आमतौर पर घर में उपलब्ध औषधियों पर आधारित हैं। इन्हें अपनाते समय स्वच्छता और सावधानी जरूरी है।

1. त्रिफला जल (सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय)

त्रिफला—आंवला, हरड़ और बहेड़ा—आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी गई है।

कैसे बनाएं:

रात में एक गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो दें।

सुबह छानकर केवल साफ पानी रखें।

इस पानी को उबालें और गुनगुना कर ठंडा होने दें।

साफ रूई या ड्रॉपर से आंख धोएं।

लाभः

सूजन कम होती है

जलन शांत होती है

मवाद का बनना कम होता है

आंखें जल्दी साफ और स्वस्थ होती हैं

आयुर्वेद में त्रिफला को "चक्षुष्यम" आंखों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है।

2. गुलाब जल (शुद्ध और बिना कैमिकल)

शुद्ध गुलाब जल आंखों पर ठंडक देता है।

उपयोगः

2–3 बूंद आंखों में डालें

या रुई पर लगाकर 10 मिनट रखें

ध्यान रखें—केवल वास्तविक, बिना कैमिकल वाला गुलाबजल ही उपयोग करें।

3. हल्दी का पानी

हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं।

कैसे करें:

एक गिलास पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उबालें

ठंडा होने पर छान लें

साफ कपड़े से आंख पोंछें

हल्दी का पेस्ट सीधे आंख पर कभी नहीं लगाना चाहिए।

4. ठंडी पट्टी (Cold Compress)

आंख की गर्मी और सूजन कम करने का सरल उपाय।

कैसे करें:

साफ कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर रखें

5–10 मिनट

दिन में 3–4 बार

यह पित्त को संतुलित करता है और जलन तुरंत कम करता है।

5. शहद का उपयोग (बहुत सावधानी से)

शहद में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण हैं।

कैसे उपयोग करें:

1 बूंद शहद को 4–5 बूंद उबले ठंडे पानी में मिलाएँ

आंखों में हल्की जलन के बाद आराम मिलता है

लेकिन यह उपाय केवल शुद्ध और असली शहद में ही उपयोगी है, बाजार के प्रोसेस्ड शहद से नुकसान हो सकता है।

6. खीरे का प्रयोग

खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से तुरंत ठंडक मिलती है।

लाभः

जलन कम

सूजन कम

आंखों को आराम

7. एलोवेरा जेल (Bitter Aloe)

आंखों के आसपास हल्के हाथों से लगाने पर सूजन कम होती है, परंतु आंख के अंदर नहीं डालना है।

आंख आने पर आयुर्वेदिक आहार-विहार

क्या खाएं?

घी (आधा चम्मच)

खीरा, तरबूज, ककड़ी

नारियल पानी

छाछ

मूंग दाल

खिचड़ी

आंवला

गिलोय पानी

ये पदार्थ पित्त को तुरंत शांत करते हैं।

क्या न खाएं?

मसालेदार भोजन

तली चीजें

गर्मी वाली चीजें (अदरक, लहसुन अधिक मात्रा में)

चाय-कॉफी

फास्ट फूड

दही

अचार

ये सभी पित्त बढ़ाते हैं और आंख की जलन बढ़ा सकते हैं।

जीवनशैली संबंधी सावधानियाँ

आंख रगड़ें नहीं

किसी की तौलिए, रुमाल, तकिया का उपयोग न करें

मोबाइल कम देखें

सूरज की तेज रोशनी से बचें

आंखों को ठंडे पानी से दिन में 3–4 बार धोएं

बच्चों के बीच संक्रमण तेजी से फैलता है—सावधान रहें

आयुर्वेदिक औषधियाँ

(डॉक्टर की सलाह के अनुसार)

त्रिफला चूर्ण – 1 चम्मच रात में

महात्रिफलाघृत – आंखों की गुनगुनी सिंचन प्रक्रिया में

च्यवनप्राश – इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए

गिलोय सत्व / गिलोय घनवटी – संक्रमण में लाभकारी

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

यदि निम्न लक्षण हों तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें—

3–4 दिन में सुधार न होना

तेज दर्द

नजर धुंधली होना

आंख में अत्यधिक मवाद

रोशनी में बहुत चुभन

बच्चों या बुजुर्गों में सूजन बढ़ना

आयुर्वेद कहता है अतियोगो हि औषधानां रोगवृद्धिकरः

अर्थात बिना सलाह दवा का उपयोग कभी-कभी रोग बढ़ा देता है।आंख आना एक सामान्य, लेकिन संक्रामक समस्या है। सही आयुर्वेदिक उपाय, स्वच्छता, और पित्त-शांत आहार से यह कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाती है। त्रिफला जल, गुलाब जल, ठंडी पट्टी और हल्के आहार का संयोजन सबसे प्रभावी माना गया है।

महायोगी अरविंद जी का दिव्य जीवन

महायोगी अरविंद जी का जीवन एक अनंत प्रकाश की किरण है, जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर समस्त सृष्टि को दिव्यता से भर देता है।इनके जीवन में हठयोग, राजयोग और लययोग का अद्भुत समन्वय था। विक्रमीय बीसवीं शताब्दी के आध्यात्मिक चिंतकों में योग साधना के क्षेत्र में वे सबसे आगे थे। जहां रामाना महर्षि ने आत्मवाद को अपनाया, महात्मा गांधी ने सत्य के रामरूप का चिंतन किया, वहीं अरविंद जी ने अंतरात्मा के शाश्वत प्रकाश में, भगवत ज्योति में जगत के अंधकार का नाश कर चराचर को अपने दिव्यीकरण सिद्धांत के संरक्षण में आत्मयोग प्रदान किया। योग का लक्ष्य केवल देहात्म भाव से ऊपर उठना और आत्मा या परमात्मा की अनुभूति नहीं था, बल्कि मन, बुद्धि, प्राण और जीवन में परमात्म ज्योति भरकर जड़ और पार्थिव प्रकृति को दिव्यता, चेतनता और अपार्थिवता प्रदान करना था। वे रूपांतरण या दिव्यीकरण उपस्थित करना चाहते थे। जीवन को सच्चिदानंद परमात्मा की समस्त दिव्य शक्ति से संपन्न करने की उनकी चेष्टा अद्भुत थी। इस पवित्र कार्य में वे अत्यधिक सफल रहे। परमात्मा की पूर्णता की अनुभूति से उन्होंने विश्व की आध्यात्मिक चेतना को प्राणवान बनाया। वे एकता, प्रेम, अमरता और चेतनता के शाश्वत गायक थे, परमात्म तत्व के विशेषज्ञ थे।

अरविंद जी ने दिव्य क्रांति उपस्थित की। भारत को आत्मचेतना दी। राजनैतिक दासता और पराधीनता की हथकड़ियों में जकड़े असंख्य प्राणियों को दिव्य जीवन प्रदान किया। स्वराज्य का दिव्यीकरण किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अनश्वर है, उसकी शक्ति अपार और अचिंत्य है, उस पर बाह्य शत्रु का वश नहीं चल सकता। अरविंद जी आत्मदर्शनिक थे, उनके आत्मदर्शन का राजप्रासाद भगवद भक्ति और शास्त्र के सिद्धांत की नींव पर स्थित था। उन्होंने अपनी योग साधना की सिद्धि भगवद भक्ति और भगवती शक्ति के अवतरण में प्रतिष्ठित की। वे विदेशी और स्वदेशी भाषाओं जैसे संस्कृत, बंगाली, ग्रीक, इटली, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि के पंडित थे। पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक विचारधाराओं का योगिक स्तर से समन्वय किया। जीवन क्रांति का दान किया।

जन्म और प्रारंभिक जीवन

महायोगी अरविंद जी का जन्म कलकत्ता के एक सुशिक्षित बंगाली परिवार में संवत 1929 विक्रमी (सन् 1872 ईस्वी, 15 अगस्त) को हुआ। उनके पिता सिविल सर्जन थे, जो अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा से बहुत प्रभावित थे। सात साल तक अरविंद जी देश में रहे। उसके बाद पिता ने उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध इंग्लैंड में किया। वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड भेजे गए। मैनचेस्टर के एक अंग्रेज परिवार में उनका पालन-पोषण हुआ। पिता ने अंग्रेज परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद जी के जीवन के किसी भी अंग पर भारतीय वातावरण का रंग न चढ़ने पाए। अरविंद जी ने प्राथमिक शिक्षा सेंट पॉल विद्यालय लंदन में प्राप्त की। वे बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। 18 साल की अवस्था में उत्तम श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त कर कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में प्रवेश किया। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए, लेकिन घुड़सवारी में असफल हो गए। वे भगवान की कृपा से योगी बनने वाले थे, आईसीएस का पद उनका स्पर्श कैसे करता? इंग्लैंड निवास काल में उन्होंने स्वदेश प्रेम का

सपना देखा। युवावस्था में ही लंदन में 'कमल-कटार' 'लोटस एंड डैगर' संस्था की स्थापना की। उनके मन में क्रांतिपूर्ण विचारों का उदय होने लगा। उन्हें अनुभव हो रहा था कि जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति उपस्थित होने वाली है और उसमें उनका भाग लेना दैव निर्दिष्ट है। इंग्लैंड निवासकाल में उन्होंने कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनमें एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति विशेष रूप से कार्यशील थी। इंग्लैंड में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ। बड़ौदा नरेश उनकी प्रतिभा और योग्यता से प्रभावित हुए। 21 साल की अवस्था में अरविंद जी भारत आए।

बड़ौदा में सेवा और अध्ययन

अरविंद जी ने बड़ौदा राज्य के भूमि-व्यवस्था विभाग में कार्य करना आरंभ किया। महाराजा बड़ौदा के व्यक्तिगत कार्य-संपादन में भी सहायता देने लगे। बड़ौदा कॉलेज के उप-प्रधानाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बड़ौदा निवास काल में उन्होंने संस्कृत और बंगला का अध्ययन किया। वे हंसस्वरूप स्वामी तथा सद्गुरु ब्रह्मानंद के संपर्क में आए। संवत 1962 विक्रमी में बंग-भंग आंदोलन छिड़ने पर उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया। वे कलकत्ता आए, स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिपूर्ण योजनाओं में सक्रिय भाग लिया। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। स्वदेशी आंदोलन को अरविंद जी ने आध्यात्मिक रूप प्रदान करना चाहा। स्वदेशी आंदोलन उनके राजनैतिक जीवन का पहला अध्याय था। स्वराज्य की मांग को उन्होंने बल दिया। संवत 1967 विक्रमी तक वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होंने क्रांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए 'वंदे मातरम' पत्र का संपादन किया। उन्होंने अंग्रेजी में 'कर्मयोगी' और बंगला में 'धर्म' नामक साप्ताहिक पत्र निकाले। कई बार उन्हें कारागार भोगना पड़ा, लेकिन वे अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहे। विक्रमीय बीसवीं शताब्दी में अरविंद जी ने पहले-पहल राजनैतिक आंदोलन को अध्यात्म से संपन्न किया। उन्होंने राजनीति में अध्यात्म का शिलान्यास किया और महात्मा गांधी ने राजप्रासाद प्रस्तुत किया।

राजनीति से योग की ओर

धीरे-धीरे अरविंद जी की चिर जागृत आध्यात्मिक चेतना ने राजनीतिक प्रवृत्ति से आगे प्रगति की। वे एकांत सेवन और योगमय जीवन का वरण करने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने 1967 विक्रमी में सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया और आत्मयोग की ओर अग्रसर हुए। अलीपुर षड्यंत्र में वे काल-कोठरी में बंद कर दिए गए। इस समय भगवान की कृपा से जेल के अधिकारियों ने उन्हें नित्य कालकोठरी के सामने घंटे-आध घंटे टहलने की अनुमति दे दी। वे पेड़ के नीचे टहला करते थे। एक दिन उनके नयनों ने पेड़ के स्थान पर साक्षात वासुदेव कृष्ण की उपस्थिति का दर्शन किया। कारागार में, कैदियों में, कण-कण में भीतर-बाहर उन्हें श्रीकृष्ण ही दिख पड़ने लगे। न्यायालय में भी उन्हें अपने प्रेमास्पद का दर्शन हुआ। वे योग साधना के लिए निकल पड़े। उन्होंने पांडिचेरी को अपनी योग-साधना और तप का क्षेत्र चुना। पांडिचेरी में योग-साधना में प्रवेश करने के पहले भी वे योगाभ्यास किया करते थे। उन्होंने पहले बिना किसी गुरु की सहायता के योग-साधना अपनाई। पांडिचेरी आगमन के दो साल पहले वे मराठी योगी विष्णु भास्कर के संपर्क में आए और उनके पथ-निर्देशन ने उन्हें पूर्ण भगवद विश्वास प्रदान किया। पांडिचेरी आश्रम में माता-फ्रेंच योगिनी के आगमन ने उनकी आध्यात्मिक साधना को बड़ा बल दिया। दोनों एक-दूसरे के दिव्य आध्यात्मिक संपर्क से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद जी ने अपनी योग-साधना में श्रीमद्भगवद्गीता तथा उपनिषदों का असाधारण महत्व स्वीकार किया।

पांडिचेरी आश्रम और साधना

पांडिचेरी का योगाश्रम उनकी साधना और आध्यात्मिक साहित्य-निर्माण का भौम प्रतीक है। उन्होंने चार साल तक कठिन योगाभ्यास किया, एकांत ही उनका साथी था। उन्होंने 'आर्य' नामक तत्वज्ञान विषयक पत्र निकाला। धीरे-धीरे पांडिचेरी आश्रम में साधकों और अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। भगवत संवाद और आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने महान प्रयत्न किया। वे जड़ जीवन में परमात्मा की चेतन सत्ता उतारने में तत्पर हुए। आत्मशक्ति, आत्मज्योति और आत्मानंद का आवाहन ही उनकी साधना की सिद्धि का प्रतीक हो उठा। वे मन, बुद्धि, प्राण और शरीर के दिव्यीकरण में लग गए। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले साधकों को आत्मध्यान की सीख दी। योगी अरविंद जी के निवास से पांडिचेरी का वातावरण तपोमय, शांत और परम पवित्र हो चला। अरविंद जी आध्यात्मिक क्रांति के स्रष्टा थे। अरविंद जी के आश्रम के संबंध में महत्वपूर्ण स्वीकृति है कि यह आश्रम दूसरे आश्रमों के समान नहीं है। यहां कोई भी संन्यासी नहीं है। संन्यासी बनकर यहां कोई रहता भी नहीं है। यहां का सारा लक्ष्य ही दूसरी तरह का है। आश्रम का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं है, इसमें रहने वाले साधक अपने आप भौतिक चेतना और योगशक्ति के समन्वय-पथ पर ले चलने का अभ्यास करते हैं। धीरे-धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ गई और आध्यात्मिक जीवन के पवित्र सौंदर्य से संपन्न आश्रम योग-साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।

श्रीमाता का योगदान

पांडिचेरी आश्रम में श्रीमाता की उपस्थिति ने अरविंद जी के आध्यात्मिक कार्य को असाधारण ढंग से आगे बढ़ाया। उनका महत्व स्वीकार करते हुए अरविंद जी ने उनके सहयोग पर प्रकाश डाला कि श्रीमाता और मैं दोनों एक हैं, अभिन्न हैं। आश्रम में वे ही सब कुछ हैं। निस्संदेह दोनों का संपर्क अध्यात्म के दिव्यतम तत्व और चिन्मय शक्ति का समन्वय-प्रतीक कहा जा सकता है। श्रीमाता अध्यात्म की देवी हैं, अरविंद जी अध्यात्म के शिव थे।

साधना पद्धति और सिद्धांत

अरविंद जी की साधना पद्धति में उच्चतम अध्यात्म यह है कि जीवन पूर्णरूप से भगवत हो जाए, भगवद ज्योति से भर जाए। संसार के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति साधना में बाधक सिद्ध होती है। जीवमात्र और चराचर के प्रति मन में निरंतर सेवा-दयाभाव रखकर भगवत चिंतन और आत्मबोध की ओर बढ़ते रहना ही जीवन का श्रेय है। साधक का सम्पूर्ण प्रेम भगवान में केंद्रित हो जाए, साधक जीवन का यही सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। अरविंद जी ने स्वीकार किया कि चित्त की शुद्धि और भगवत शक्ति का अवतरण दोनों का काम एक साथ चलता है। दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक स्थिरता और दृढ़ता के साथ दोनों एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं, साधना का यही सामान्य क्रम है। अरविंद जी ने योगाभ्यास को साधना का अभिप्राय बताया। उन्होंने कहा कि साधना का फल पाने के लिए तथा निम्न प्रकृति पर विजय पाने के लिए अपनी संकल्प-शक्ति को एकाग्र करना ही तपस्या है। भगवान की पूजा करना, उनसे प्रेम करना, उन्हें आत्म समर्पण करना, पाने की अभिप्सा करना, उनका नाम जपना, प्रार्थना करना आराधना है। समाधिस्थ होकर चेतना एकाग्र करना ध्यान है। अरविंद जी ने तपस्या, आराधना और ध्यान-साधना के अंगों को पांडिचेरी आश्रम के तपोमय जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ कर दिया।

महासमाधि और विरासत

संवत 2007 विक्रमी में (सन् 1950 ईस्वी में 5 दिसंबर को आधी रात के बाद लगभग 1.5 बजे) अरविंद जी महासमाधि में योगस्थ हो गए। उनका शरीर विकृत नहीं हुआ। 111 घंटे के बाद 9 दिसंबर को हजारों की उपस्थिति में उनकी अंत्येष्टि क्रिया साधारण विधि से संपन्न हुई। वे अध्यात्म साम्राज्य के योगी सम्राट थे। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी महती काव्यकृति सावित्री समाप्त कर दी। पांडिचेरी आश्रम में स्थित उनकी महासमाधि पर अंकित शब्द हैं-

"हमारे देवता की भौम समाधि, हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आप के सामने, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तपस्या और आशा तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संकल्प-संपादन, प्रयत्न, प्रस्तुति और समस्त उपलब्धि का व्रत अनुष्ठान किया, हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपकी अनुगृहीत का विस्मरण न करें।"

पांडिचेरी आश्रम की परम अधिष्ठात्री शक्ति श्रीमाता की यह श्रद्धांजलि समस्त भारत और विश्व की विश्वात्मा महायोगी अरविंद जी के प्रति प्रणति की प्रतीक है। भगवान करे यह वाणी शाश्वत, दिव्य, अमिट, अक्षर तथा सर्वदा आनंदमयी हो।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

मौनी अमावस्या पर संगम में संत और सत्ता आमने-सामने

जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर, मेला प्रशासन से माफी और ससम्मान स्नान की मांग

@ शोभित यादव

माघ मेला में मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर संगम जाने से रोके गए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्वयं को अपमानित किए जाने और अपने शिष्यों के साथ पुलिस की अभद्रता से आहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से अन्न-जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक मेला प्रशासन उनसे इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान संगम में स्नान नहीं कराया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यह केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि संत समाज के सम्मान का प्रश्न है। उन्होंने मेला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर उन्हें और उनके शिष्यों को अपमानित किया गया।

प्रशासन की चुप्पी से बढ़ी नाराजगी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि घटना के बाद से अब तक मेला प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, गृह सचिव मोहित गुप्ता, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और सीओ विनीत सिंह को पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है।धरने पर बैठे स्वामी का कहना है कि यदि प्रशासन सच में संत समाज का सम्मान करता है, तो अब तक उनसे संवाद करने जरूर आता। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी का न आना यह दर्शाता है कि प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है।

मीडिया से बातचीत में सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सोमवार को मीडिया से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन सरकार उन्हें मरवाना चाहती थी। उनका कहना था कि इतनी भारी भीड़ के बीच उन्हें जानबूझकर रोका गया, धक्का-मुक्की की स्थिति बनाई गई और हालात ऐसे कर दिए गए कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, “योगी सरकार चापलूस संतों को पसंद कर रही है। जो संत सत्ता के सवाल उठाते हैं, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। पालकी से उतरने का दबाव भी इसी साजिश का हिस्सा था।”

अपमान और अभद्रता का आरोप

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के दिन हुई पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह उन्हें पालकी से उतरने के लिए मजबूर किया गया, किस तरह उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की और किस तरह उन्हें बिना स्नान कराए वापस लौटने को मजबूर कर दिया गया।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, बटुकों की चोटी तक खींची गई और संतों से अपमानजनक भाषा में बात की गई। स्वामी का कहना है कि यह सब किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

गोहत्या और गोरक्षा का मुद्दा भी उठाया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गोहत्या कराकर राजनीति करने वाले लोग सक्रिय हैं, जबकि वे गोरक्षा का अभियान चला रहे हैं। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के मुद्दे पर वे लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और इसी कारण उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।स्वामी ने यहां तक कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और मौनी अमावस्या की घटना उसी साजिश का हिस्सा थी।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

उल्लेखनीय है कि रविवार को माघ मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर से पहिया लगी पालकी पर सवार होकर शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे। यह यात्रा पारंपरिक शोभायात्रा के स्वरूप में थी।लेकिन संगम पहुंचने से पहले पांटून पुल नंबर दो के पास पुलिस ने उनकी शोभायात्रा को रोक दिया। पुलिस का कहना था कि संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और सुरक्षा के लिहाज से शोभायात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कहा कि वह पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए जाएं।

शिष्यों का फूटा आक्रोश

पुलिस के इस रवैये से स्वामी के शिष्य नाराज हो गए। उनका कहना था कि यह संतों का अपमान है और शोभायात्रा उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसी बात को लेकर पुलिस और शिष्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई।आरोप है कि इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सख्ती करनी पड़ी।

शिष्यों को हिरासत में लिया गया

झड़प के बाद पुलिस ने कुछ शिष्यों को हिरासत में ले लिया। इनमें प्रतक्षचैतन्य मुकुंदानंद गिरि सहित कई लोग शामिल थे। शिष्यों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीटा और संगम थाना ले जाया गया।धक्का-मुक्की के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी का छत्र-चंवर टूटकर गिर गया। अधिकारियों ने उनसे व्यवस्था के अनुरूप स्नान करने की अपील की, लेकिन स्वामी इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया।

धरने पर बैठे स्वामी

इस पूरी घटना से आहत होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक प्रशासन अपनी गलती नहीं मानता, तब तक वह अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे।धरने के दौरान उनके शिष्य और समर्थक भी मौजूद हैं। पूरे मामले ने अब संत समाज में भी नाराजगी पैदा कर दी है।घटना के कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुए हैं। इन वीडियो में पुलिसकर्मी बटुकों को पीटते और उनकी चोटी खींचते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो में संतों से पुलिसकर्मियों की अभद्र बातचीत भी नजर आ रही है।

संत समाज में बढ़ती नाराजगी

प्रशासन का कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद थे। भीड़ अत्यधिक होने के कारण संतों की शोभायात्रा पर रोक लगाई गई थी। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।पुलिस का दावा है कि शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।इस पूरे घटनाक्रम के बाद संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। कई संतों का कहना है कि प्रशासन को संतों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इतनी भारी भीड़ में सुरक्षा सर्वोपरि होती है।

राजनीतिक रंग लेने लगा मामला

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं।फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रुख पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिना माफी और ससम्मान स्नान के वह धरना समाप्त नहीं करेंगे। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है।ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले घंटों में मेला प्रशासन और सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है। संत और सत्ता के बीच खड़ा यह विवाद माघ मेले की शांति और गरिमा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

वृंदावन में श्री सुदामा कुटी का शताब्दी समारोह बना संत शक्ति का महाकुंभ

मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी, जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, नाभा पीठाधीश्वर श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज सहित अनेक विशिष्ट संतों की उपस्थिति, अध्यात्म और राष्ट्र चेतना पर हुआ मंथन

@ भारतश्री ब्यूरो

ब्रजभूमि वृंदावन में स्थित श्री सुदामा कुटी का शताब्दी समारोह आध्यात्मिक चेतना, संत शक्ति और राष्ट्रीय मूल्यों का भव्य संगम बनकर सामने आया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित संत, महंत और धर्माचार्य एक मंच पर उपस्थित रहे। पूरा वातावरण श्रद्धा, साधना और सनातन चेतना से ओतप्रोत नजर आया।

देश के प्रतिष्ठित संतों की गरिमामयी उपस्थिति

शताब्दी समारोह में मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी, जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, नाभा पीठाधीश्वर श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज सहित अनेक विशिष्ट संतों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। संतों की इस सभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन की धरती पर सनातन परंपरा साकार हो उठी हो।

श्री मोहन भागवत ने संत परंपरा को बताया राष्ट्र की आत्मा

समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा कि संत परंपरा भारत की आत्मा है। उन्होंने कहा कि जब समाज कठिन दौर से गुजरता है, तब संत ही उसे दिशा दिखाते हैं। उन्होंने संतों के त्याग, तपस्या और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का आधार धर्म और अध्यात्म है।

जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का ओजस्वी संबोधन

समारोह में जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का संबोधन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने संतों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संतों की साधना के कारण आज करोड़ों लोग ऐसी समस्याओं से समाधान पा रहे हैं, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा ने लाइलाज मान लिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वहां आयुर्वेद और अध्यात्म ने काम किया।

अध्यात्म हटेगा तो सब समाप्त हो जाएगा

जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि अगर जीवन से अध्यात्म को हटा दिया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना समाज दिशाहीन हो जाता है। अगर धर्म हट गया तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। उनका कहना था कि अध्यात्म ही मनुष्य को संयम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाता है।

भारत की शक्ति पर जगद्गुरु का बड़ा वक्तव्य

अपने संबोधन में जगद्गुरु ने भारत की शक्ति को अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उससे बड़ी न कोई शक्ति थी, न है और न कभी होगी। यह शक्ति ही परा सत्य का स्वरूप है। इसी शक्ति ने भारत को हजारों वर्षों तक जीवित रखा और आगे भी यही शक्ति देश का मार्गदर्शन करती रहेगी।

WORLD HUMANITY PARLIAMENT का उल्लेख

जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 160 देशों ने मिलकर उन्हें WORLD HUMANITY PARLIAMENT का अध्यक्ष चुना है। उन्होंने कहा कि यह भारत के अध्यात्म और सनातन संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है।

वृंदावन में 108 एकड़ में भव्य परियोजना

जगद्गुरु ने वृंदावन में चल रही एक बड़ी आध्यात्मिक परियोजना की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि वृंदावन में 108 एकड़ भूमि ली गई है, जहां बांके बिहारी और मां राधा जी का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। इसके साथ ही वहां एक विश्वविद्यालय, गोशाला और कई अन्य अद्भुत एवं जनकल्याणकारी योजनाएं भी विकसित की जाएंगी।

संत समाज को दिया आमंत्रण

अपने संबोधन के अंत में जगद्गुरु श्री कुमार स्वामी जी ने सभी संतों को इस भव्य परियोजना का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प है।श्री सुदामा कुटी का शताब्दी समारोह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा बल्कि संत समाज की एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। विभिन्न परंपराओं और पीठों से आए संतों ने एक स्वर में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के संरक्षण की बात कही।

श्रद्धालुओं में दिखा अपार उत्साह

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। संतों के दर्शन और उनके विचारों को सुनने के लिए दूर-दूर से लोग वृंदावन पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसा अवसर जीवन में बार-बार नहीं आता, जब इतने बड़े संत एक साथ एक मंच पर दिखाई दें। पूरे समारोह के दौरान वृंदावन की धरती सनातन चेतना से आलोकित नजर आई। भजन, मंत्रोच्चार और संतों के विचारों ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शताब्दी समारोह ने यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा आज भी जीवित है और संत परंपरा के माध्यम से समाज को दिशा देती रहेगी।कुल मिलाकर श्री सुदामा कुटी का यह शताब्दी समारोह ऐतिहासिक बन गया। यह आयोजन अध्यात्म, धर्म, राष्ट्र और मानवता के मूल्यों को एक साथ स्थापित करने वाला सिद्ध हुआ। संतों के विचार और संकल्प आने वाले समय में समाज को नई दिशा देंगे, ऐसा विश्वास श्रद्धालुओं ने व्यक्त किया।

ग्रीनलैंड बना महाशक्तियों का अखाड़ा

ट्रम्प बोले— ग्रीनलैंड जरूरी, NATO और डेनमार्क में बेचैनी

@ मनीष पांडेय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रम्प के इस बयान के बाद अमेरिका, डेनमार्क और NATO के बीच हलचल तेज हो गई है। आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और ग्रीनलैंड एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है।ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने इसे भविष्य की रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका इस इलाके को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ट्रम्प के इस बयान को सिर्फ कूटनीतिक दबाव नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है।

NATO चीफ से बातचीत, दावोस में बैठक की तैयारी

ट्रम्प ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी NATO के महासचिव मार्क रुटे से फोन पर "बहुत अच्छी बातचीत" हुई है। बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग-अलग पक्षों के साथ बैठक की जाएगी। दावोस बैठक को ग्रीनलैंड विवाद में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जहां अमेरिका, NATO और यूरोपीय देशों के रुख साफ हो सकते हैं।ट्रम्प ने खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि ताकत के जरिए ही दुनिया में शांति कायम की जा सकती है और यह क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है। उनके इस बयान ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि ट्रम्प कूटनीति से ज्यादा शक्ति आधारित नीति में विश्वास रखते हैं।

NATO चीफ का निजी संदेश साझा करना बना चर्चा का विषय

ट्रम्प ने NATO चीफ मार्क रुटे का एक निजी संदेश भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसे लेकर यूरोप में असहजता देखी जा रही है। इस संदेश में रुटे ने ट्रम्प की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सीरिया में जो हासिल किया है, वह अविश्वसनीय है। उन्होंने यह भी लिखा कि दावोस में अपने मीडिया इंटरव्यू में वह सीरिया, गाजा और यूक्रेन में ट्रम्प की भूमिका का जिक्र करेंगे।रुटे ने अपने संदेश में ग्रीनलैंड को लेकर आगे का रास्ता निकालने की प्रतिबद्धता भी जताई और ट्रम्प से जल्द मुलाकात की इच्छा जाहिर की। ट्रम्प ने इस संदेश के लिए रुटे का धन्यवाद दिया। हालांकि, NATO के भीतर यह सवाल उठने लगा है कि निजी बातचीत को सार्वजनिक करना कितनी कूटनीतिक समझदारी थी।

ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विमान की तैनाती

ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर डेनमार्क से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। यह विमान पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेगा, जो पहले से ही अमेरिकी मिसाइल चेतावनी प्रणाली का अहम केंद्र है।NORAD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा कि यह तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों का हिस्सा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी। NORAD के मुताबिक, यह कदम अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क के बीच लंबे समय से चली आ रही रक्षा साझेदारी के तहत उठाया गया है।

डेनमार्क की जवाबी तैयारी

ट्रम्प की धमकियों के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कई विमान डेनमार्क के सैनिकों और सैन्य उपकरणों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचे। इससे साफ है कि डेनमार्क इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।डेनमार्क पहले से ही ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात किए हुए है। इसके अलावा 14 सदस्यीय 'सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल' भी वहां मौजूद है, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करता है। यह पेट्रोल यूनिट बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए जानी जाती है।

NATO की एकजुटता का संदेश

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में तैनात बलों को जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने माना कि यह संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है कि NATO एकजुट है। डेनमार्क की अगुआई में चल रहा 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस' एक सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद यह परखना है कि भविष्य में अगर ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने की जरूरत पड़ी, तो उसकी तैयारी कैसी होगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस अभ्यास का फोकस आर्कटिक क्षेत्र में सहयोगी देशों के बीच तालमेल बढ़ाने पर है।

आगे की योजना: ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री

आगे चलकर इससे भी बड़े मिशन की योजना बनाई जा रही है, जिसे 'ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री' नाम दिया गया है। यह एक NATO मिशन होगा, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाना और किसी भी संभावित खतरे का सैन्य जवाब देने की क्षमता मजबूत करना है।हालांकि, यह मिशन तुरंत शुरू नहीं होगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के मुताबिक, ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री को लागू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल जोर तैयारी और रणनीतिक योजना पर है।

क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला सकते हैं?

ट्रम्प 2019 से ही ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात करते रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ चुका है। लेकिन कानूनी रूप से यह मामला काफी जटिल है।ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और अमेरिका तथा डेनमार्क दोनों NATO के सदस्य हैं। NATO के नियमों के मुताबिक, एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश पर कब्जा नहीं कर सकता। ऐसा करना NATO संधि के खिलाफ होगा। NATO का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।ग्रीनलैंड अगर अमेरिका से जुड़ना चाहता है, तो पहले उसे स्वतंत्र होना होगा। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनिश संसद की मंजूरी जरूरी है।

ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है?

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और अटलांटिक महासागर के मध्य क्षेत्र के करीब है। सैन्य दृष्टि से यह यूरोप, रूस और आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखने के लिए अहम ठिकाना है।यहां अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी-चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं। चीन पहले से ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखता है, जिसे अमेरिका कम करना चाहता है।ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नई समुद्री व्यापारिक राहें खुल रही हैं। इन रास्तों पर नियंत्रण भविष्य में वैश्विक व्यापार और सैन्य रणनीति दोनों के लिए अहम होगा।

बढ़ता तनाव, बढ़ती अनिश्चितता

फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी और सैन्य तैयारियों से यह साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाएगा। ट्रम्प का सख्त रुख, NATO की सक्रियता और डेनमार्क की सतर्कता यह संकेत दे रही है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम मोर्चा बन चुका है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचेगी यूपी की चार ट्रांसजेंडर

नेशनल परेड में स्पेशल गेस्ट बनेंगी गोरखपुर के गरिमा गृह से जुड़ी चार बेटियां

@ सौम्या चौबे

26 जनवरी का दिन इस बार उत्तर प्रदेश के लिए खास होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर देश की सबसे बड़ी परेड में यूपी की चार ट्रांसजेंडर महिलाओं को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये चारों गोरखपुर स्थित गरिमा गृह से जुड़ी हुई हैं और अपने संघर्ष, हौसले और सामाजिक योगदान के बल पर राष्ट्रीय मंच तक पहुंची हैं।ये चारों 24 जनवरी को प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पहुंचेंगी। 25 जनवरी को वे राजधानी के प्रमुख म्यूजियम और नेशनल वॉर मेमोरियल का भ्रमण करेंगी। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के पास आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगी। यह न सिर्फ उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गर्व का क्षण भी है।

केंद्र सरकार ने मांगी थीं प्रोफाइल

गरिमा गृह की संचालिका एकता महेश्वरी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देशभर के ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोगों की प्रोफाइल मांगी गई थीं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत से करीब 200 ऐसे लोगों की प्रोफाइल भेजी गई, जो अपने स्तर पर समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है।इनमें से लगभग 50 लोगों का चयन किया गया है, जिनमें यूपी से गोरखपुर की चार ट्रांसजेंडर को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। एकता महेश्वरी के मुताबिक, उन्हें इसकी जानकारी ईमेल के जरिए मिली। उन्होंने कहा कि यह चयन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ा सम्मान है।

संघर्ष से सम्मान तक का सफर

इन चारों की जिंदगी आसान नहीं रही। समाज, परिवार और हालात से लड़ते हुए इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज जब ये राष्ट्रपति की मौजूदगी में परेड देखेंगी, तो वह पल उनके पूरे संघर्ष को सार्थक कर देगा।कुशीनगर जिले में जन्मी दीपिका का बचपन बेहद कठिन रहा। वह बताती हैं कि जन्म के समय उनका नाम दीपक रखा गया था। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, उनका व्यवहार लड़कियों जैसा होने लगा। घरवालों और समाज को यह स्वीकार नहीं था।दीपिका कहती हैं कि पिता ने उन्हें कई बार मारा-पीटा और साफ शब्दों में कहा, "अगर इस घर में रहना है तो लड़कों की तरह रहो, वरना घर छोड़ दो।" यह सुनकर वह अंदर से टूट गईं। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। जब सामान पैक करने लगीं, तो मां रोने लगीं और उन्हें रोक लिया।घर में रुक तो गईं, लेकिन ताने और मानसिक प्रताड़ना बढ़ती गई। बाहर लोग मजाक उड़ाते, अंदर घरवाले समझने को तैयार नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर वह कमाने लगेंगी, तो शायद परिवार उन्हें स्वीकार कर ले।इसी सोच के साथ उन्होंने कंप्यूटर कोर्स शुरू किया। वहीं उनकी मुलाकात गरिमा गृह से जुड़े एक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें एकता महेश्वरी से मिलवाया। दीपिका कहती हैं कि वहीं से उन्हें पहली बार खुद को समझने और स्वीकार करने की ताकत मिली।इसके बाद वह नौकरी के बहाने घर से निकलीं और गोरखपुर आ गईं। यहां से दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली में भी संघर्ष कम नहीं था। लोगों के ताने सहने पड़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक NGO में काम करते हुए मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया।

"डॉक्टरों ने प्रूफ के लिए पैंट उतारने को कहा"

दीपिका बताती हैं कि लड़के के शरीर में लड़की की तरह रहना आसान नहीं था। वह जहां भी जातीं, लोग घूरते, चिढ़ाते और दूरी बना लेते। उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का फैसला किया और एक सरकारी अस्पताल पहुंचीं।वहां डॉक्टरों ने उनसे प्रूफ के लिए पैंट उतारने को कहा। यह पल उनके लिए बेहद डरावना था। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग आईं। बाद में एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने सर्जरी करवाई।आज दीपिका दिल्ली में अपना खुद का सैलून चला रही हैं। मॉडलिंग भी करती हैं। वह कहती हैं कि आज वह वो सब कर पा रही हैं, जो उन्हें पसंद है। अब किसी का डर नहीं है। नेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है, तो खुद पर गर्व होता है।

पिता ने कहा अपना रास्ता देखो, पढ़ाई का खर्च बंद कर दिया

कुशीनगर की रहने वाली हीर की कहानी भी दर्द और संघर्ष से भरी है। जन्म के समय उनका नाम अमित रखा गया था। लेकिन वह कहती हैं कि उनके अंदर शुरू से ही एक लड़की थी। बचपन में उन्हें क्रीम, लिपस्टिक और बिंदी लगाना अच्छा लगता था।उनकी चाल और हरकतों को देखकर बच्चे, पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें छक्का और हिजड़ा कहकर चिढ़ाते थे। डर के कारण उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। खेलना-कूदना बंद कर दिया। पढ़ाई में उनका मन खूब लगता था और वह क्लास में टॉप करती थीं।9वीं से 12वीं के बीच का समय उनके लिए सबसे कठिन रहा। घर और बाहर हर जगह उन्हें चिढ़ाया गया। कोई समझने को तैयार नहीं था। वह डिप्रेशन में चली गईं और परीक्षा में फेल होने लगीं।जब उन्हें पता चला कि ट्रांसजेंडर भी एक पहचान होती है, तब तक हालात बिगड़ चुके थे। परिवार को जब सच्चाई पता चली, तो पिता ने कहा, "अपना रास्ता देखो।" इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया।

परिवार ने दिया साथ, लेकिन समाज से आज भी डर

गोरखपुर की लाडो की कहानी थोड़ी अलग है। वह बताती हैं कि जन्म के समय वह लड़का थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनके अंदर लड़के और लड़की दोनों के गुण आने लगे। बाहर निकलने पर लोग ताने देते थे। वह डिप्रेशन में चली गईं।एक दिन उन्होंने घर में सबको सच्चाई बता दी। लाडो कहती हैं कि उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। यही वजह है कि वह खुद को संभाल पाईं।2019 में वह गरिमा गृह से जुड़ीं। वहीं काम शुरू किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च से डिप्लोमा किया। फिलहाल वह कल्याण साथी पोर्टल में काम कर रही हैं।लाडो कहती हैं कि वह आज ट्रांसजेंडर के रूप में जी रही हैं, लेकिन अभी भी खुलकर समाज के सामने अपनी पहचान नहीं रख सकतीं। उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके परिवार को परेशान किया जाएगा।

"कहा गया — पढ़ाई हमारे लिए नहीं बनी"

हीर मुंबई पहुंचीं, लेकिन वहां किसी ने नौकरी नहीं दी। फिर देवरिया आईं और EDCA कोर्स में दाखिला लिया। फीस 12 हजार रुपए थी, उनके पास सिर्फ 4 हजार थे।इस दौरान वह LGBT कम्युनिटी से मिलीं। जब उन्होंने पढ़ाई की इच्छा जताई, तो कुछ लोगों ने उन्हें डांट दिया। कहा गया कि पढ़ाई हमारे लिए नहीं बनी है, नाच-गा और बधाई मांग।यह सुनकर हीर वहां से भाग निकलीं। एक दोस्त की मदद से वह गोरखपुर के गरिमा गृह पहुंचीं। आज वह दो फेलोशिप के जरिए जेंडर और संविधान पर काम कर रही हैं।हीर कहती हैं कि आज भी उनके पिता को उनकी सच्चाई नहीं पता। उन्हें लगता है कि वह गोरखपुर में पढ़ाई कर रही हैं। चाचा-चाची और रिश्तेदार उनकी मां को ताने मारते हैं। आज भी वह घर जाने से डरती हैं।

गणतंत्र दिवस पर मिलेगा सम्मान

इन चारों की कहानियां बताती हैं कि पहचान की लड़ाई कितनी कठिन होती है। घर से बेघर होना, समाज के ताने, सिस्टम की बेरुखी और मानसिक यातनाएं झेलने के बाद आज ये चारों देश के सबसे बड़े मंच पर पहुंच रही हैं।26 जनवरी को जब ये राष्ट्रपति की मौजूदगी में परेड की साक्षी बनेंगी, तो वह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि उस सोच की जीत होगी, जो बराबरी और सम्मान की बात करती है।यह दिन इन चारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक बनकर सामने आएगा।

“पाकिस्तान अपने बनने का असली मकसद पूरा करने की ओर”

लाहौर में आसिम मुनीर का दावा, इस्लामिक पहचान को केंद्र में रखकर सेना की नई दिशा

@ रिंकू विश्वकर्मा

पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर देश की इस्लामिक पहचान और टू नेशन थ्योरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का “असली मकसद” अब पूरा होने वाला है। यह बात उन्होंने रविवार को लाहौर में पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल से बातचीत के दौरान कही।

आसिम मुनीर लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा (रिसेप्शन) में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज समेत कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसी मौके पर अनौपचारिक बातचीत में मुनीर ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति, उसकी अंतरराष्ट्रीय भूमिका और भविष्य की दिशा पर खुलकर अपनी बात रखी।

“अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक मौका दिया”

आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक अवसर दिया है, ताकि वह अपने बनने के उद्देश्य को पूरा कर सके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आज उसे इस्लामिक देशों के बीच एक खास पहचान हासिल है। आने वाले समय में यह अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी।मुनीर ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे देश को मिली पहचान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी स्तर पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहना मिल रही है, तो वह भी अल्लाह की मेहरबानी है।

“पाकिस्तान की हालत में सुधार हुआ”

आर्मी चीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की आर्थिक और वैश्विक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान को लेकर नजरिया बदला है और देश को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर से गंभीरता से लिया जा रहा है।हालांकि, पाकिस्तान की जमीनी आर्थिक हकीकत इससे अलग तस्वीर पेश करती है। देश अभी भी कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सेना प्रमुख का बयान यह संकेत देता है कि सैन्य नेतृत्व हालात को सकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका और ट्रम्प कनेक्शन की चर्चा

आसिम मुनीर के इस बयान को हाल के अंतरराष्ट्रीय

घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकातों में पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चर्चा हुई थी।कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों और कच्चे तेल के संसाधनों का भरोसा दिलाया है, हालांकि इन संसाधनों को लेकर अब तक कोई ठोस और सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद पाकिस्तानी नेतृत्व इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बढ़ती अहमियत के रूप में पेश कर रहा है।

कट्टर इस्लामिक लाइन पर लगातार जोर

आसिम मुनीर बीते कुछ समय से लगातार इस्लामिक विचारधारा और टू नेशन थ्योरी को लेकर सख्त और स्पष्ट बयान देते रहे हैं। अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी ही पाकिस्तान की बुनियाद है।उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बुनियादी फर्क है और दोनों एक नहीं, बल्कि अलग-अलग राष्ट्र हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमा पर रखी गई है और इस सोच को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है।उनके ये बयान पाकिस्तान की सेना की वैचारिक दिशा को साफ तौर पर दिखाते हैं, जिसमें मजहब को केंद्रीय भूमिका दी जा रही है।

पुराने सेना प्रमुखों से अलग हैं आसिम मुनीर

आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पिछले सेना प्रमुखों से बिल्कुल अलग माना जाता है। इससे पहले के ज्यादातर आर्मी चीफ पश्चिमी सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षित पेशेवर सैनिक थे, जो सार्वजनिक रूप से धर्म और राजनीति से दूरी बनाए रखते थे।इसके उलट आसिम मुनीर हाफिज-ए-कुरान हैं और मजहब उनकी सार्वजनिक छवि का अहम हिस्सा है। वह पाकिस्तान के पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI दोनों की कमान संभाली है। उनकी अगुआई में पाकिस्तानी सेना खुद को सिर्फ देश की रक्षा करने वाली ताकत नहीं, बल्कि इस्लाम की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में भी पेश कर रही है।

सेना की भाषा और प्रतीकों में बदलाव

आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना की भाषा और प्रतीकों में भी बदलाव देखा जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय विद्रोही संगठनों को अब “फितना अल-खवारिज” और फितना अल-हिंदुस्तान जैसे नाम दिए जा रहे हैं।सेना की ओर से इन समूहों को गुमराह ताकतें बताया जाता है और उन पर भारत समर्थित होने का आरोप लगाया जाता है। यह भाषा पहले के मुकाबले ज्यादा धार्मिक और वैचारिक नजर आती है, जो पाकिस्तान के सुरक्षा विमर्श को नए रूप में ढाल रही है।

CDF और COAS दोनों पदों पर एक साथ

पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर 2025 को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। वह पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF और COAS दोनों जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी, जिसे मंजूरी मिलते ही मुनीर को देश के सबसे ताकतवर पद पर बैठा दिया गया।

27वां संवैधानिक संशोधन और परमाणु कमान

12 नवंबर को पाकिस्तानी संसद ने सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसी संशोधन के तहत CDF का पद बनाया गया और आसिम मुनीर को इस पर नियुक्त किया गया।इस पद के साथ ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। यानी अब पाकिस्तान की सैन्य रणनीति, तीनों सेनाओं का नियंत्रण और परमाणु फैसले एक ही व्यक्ति के हाथ में हैं। इसी वजह से आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स माना जा रहा है।इसी साल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर भी पदोन्नत किया गया। यह पद पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में बेहद दुर्लभ माना जाता है और आमतौर पर असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाता है।

सेना प्रमुख बनने से CDF तक का सफर

29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उस समय उनका कार्यकाल तीन साल का था, जो 28 नवंबर 2025 को खत्म होना था। लेकिन संवैधानिक बदलाव और नए पद के सृजन के बाद उनका प्रभाव और कार्यकाल दोनों बढ़ गए।आसिम मुनीर के हालिया बयान यह साफ करते हैं कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना अब खुलकर इस्लामिक पहचान और वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ा रही है। जहां समर्थक इसे पाकिस्तान की आत्मा से जुड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे देश के लिए और ज्यादा कट्टर रास्ते की ओर बढ़ना मानते हैं।एक तरफ आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ सेना प्रमुख का यह दावा कि पाकिस्तान अपने असली मकसद को हासिल करने जा रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि यह मकसद देश को मजबूती देगा या नई मुश्किलों की ओर ले जाएगा।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

वृंदावनी धुन

कीर्तन जो मैं गाता हूँ
यमन राग है जो रात

अँधेरा वृंदावनी धुनों के साथ
जो मेरे पास सोता है

वह मेरी वासना है
वह मेरी सुबह की ओस है

वह मेरे नहाने का पानी है
वह है मेरे होंठों की मिठास

बात जो संचारी में
रुद्रवीणा की लय में झूम उठती है

मैं एक सुंदर गीत हूँ
मैं एक सुंदर कविता हूँ

मैं रवींद्रतीर्थ में एकाकी उदासी खींचता हूँ
राधा की आँख...

मैं विसर्जन हूँ
मैं कृष्णचुरा गीत हूँ

मैं अपना अंश हूँ
कण-कण में संधिपूजा की पत्तियाँ हूँ मैं

मैं रोता हुआ,
धूल भरा पागल भजन हूँ

मैंने तुम्हें सब कुछ दिया
अभिसार,

तुम ही वैष्णव बनो...

मेरे लिए कोई कभी नहीं रोया

मेरे जन्म लेने के समय
एक गंभीर साँस फैल गई थी—

हमारे मध्यवित्त संसार में
बच्चे का रुदन सुनकर

ख़ुश होने का यत्न करता
न करता संसार

समझ गया—
कन्या संतान आई

शर्म से झुक जाने वाली
माँ मेरी

और नानी
आँसू छिपाने की कोशिश करती हुई

बेसँभाल हो गई थीं
मेरी दादी मुँह मोड़कर बोल उठी : न्याका

मेरे लिए कोई नहीं रोया कभी
मेरी किशोरी माँ ने

मुझे सिखाया—
रोना है तो छिपकर

ताकि कोई न जान पाए
मैं भी

तब से
ख़ुद को

इस संसार की
अतिथि समझकर

दूसरे घरों का
सपना देखती हुई

ख़ुद के लिए
आँसू बहाना भूल गई

मैं जान चुकी थी :
मेरे आँसू संसार को नष्ट कर देंगे

मैं समझ गई थी :
मैं और मेरा भाई एक नहीं हैं

मुझे पता चल गया था :
मेरी इच्छाएँ ग़लती हैं

मैं भी मेरे भाई की भाँति रोना चाहती थी
मैं भी अपने रोने की आवाज़ सुनना चाहती थी

मैं भी चाहती थी :
मेरी पीड़ा का अनुवाद करना

मेरी कष्ट को थोड़ा हल्का करना
मेरी चाहत को सबके सामने लाना

मैंने अपनी माँ की ओर देखा
मैंने अपनी दादी की ओर देखा

मैं अपनी चाची, बुआ और बड़ी बहनों की ओर देखती थी
सबकी आँखें सूखी

और सूखी
और सूखी...

मैंने चुप रहना सीख लिया
मैंने दुनिया से कुछ भी न चाहना सीख लिया

मैंने दिखावा करना सीख लिया
मैं एक अजनबी की तरह ख़ुद को भूल गई

मैं अपने लिए रोना भूल गई
कोई भी मेरे लिए रोना भूल गया...

बेबी शॉ

नई पीढ़ी की सुपरिचित-सम्मानित बांग्ला कवि-गद्यकार-अनुवादक।
इक्कीस पुस्तकें प्रकाशित। हिंदी में भी कविताएँ लिखती हैं।

142 करोड़ की आबादी में अकेलापन

चीन का वायरल ऐप 'आर यू डेड?' ने क्यों छेड़ी बहस?

चीन में हाल ही में एक ऐप बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है, जिसका नाम है 'सी ले मे' या इंग्लिश में 'आर यू डेड?'। यह ऐप उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अकेले रहते हैं। इसका काम बहुत आसान है: यूजर को हर दिन ऐप पर एक बटन दबाकर चेक-इन करना होता है, जैसे कि कहना हो 'मैं ठीक हूं'। अगर कोई दो दिन तक चेक-इन नहीं करता, तो ऐप अपने आप यूजर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज देता है। यह ऐप 2025 के मध्य में लॉन्च हुआ था, लेकिन जनवरी 2026 में यह अचानक वायरल हो गया। ऐप्पल ऐप स्टोर पर यह सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पेड ऐप बन गया, जहां इसकी कीमत लगभग 8 युआन यानी करीब 90 रुपये है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, खासकर युवा जो शहरों में अकेले रहते हैं। इसकी सफलता का कारण चीन की बढ़ती अकेले रहने वाली आबादी है, जहां लोग काम के लिए परिवार से दूर चले जाते हैं। लेकिन इस ऐप ने सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं उठाई, बल्कि पूरे देश में अकेलेपन पर एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे वीबो पर लोग कह रहे हैं कि यह ऐप समाज की एक छिपी समस्या को सामने ला रहा है। कुछ यूजर्स इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे गंभीरता से देखते हैं। डेवलपर्स का कहना है कि यह ऐप एक छोटी टीम ने बनाया, जो खुद युवा हैं और अकेले रहने के खतरे समझते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐप की लोकप्रियता ने कॉपीकैट ऐप्स भी पैदा कर दिए, जैसे 'आर यू अलाइव?'। कुल मिलाकर, यह ऐप दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे रोजमर्रा की समस्याओं का हल दे सकती है, लेकिन साथ ही समाज की गहरी परेशानियों को भी उजागर करती है। इसकी वजह से चीन में अकेले रहने वालों की संख्या पर फिर से ध्यान गया है, जो करीब 92 मिलियन है। यह आंकड़ा बताता है कि 142 करोड़ की बड़ी आबादी में भी लोग कितने अलग-थलग महसूस करते हैं। यह ऐप न सिर्फ सेफ्टी टूल है, बल्कि एक आईना भी, जो समाज को अपनी सच्चाई दिखा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ऐप्स भविष्य में और जरूरी हो जाएंगी।

चीन में अकेलेपन की बढ़ती समस्या: कारण और आंकड़े

चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 142 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में करीब 92 मिलियन लोग अकेले रहते हैं, और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण शहरीकरण है, जहां युवा काम की तलाश में गांवों से शहरों में आ जाते हैं और परिवार से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा, पुरानी 'वन-चाइल्ड पॉलिसी' की वजह से परिवार छोटे हो गए हैं, और बुजुर्गों को अकेले रहना पड़ता है। 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 60 साल से ऊपर के करीब 200 मिलियन लोग हैं, जिनमें से कई अकेले हैं। अकेले रहने से मौत का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो कोई मदद के लिए नहीं होता। उदाहरण के लिए, पिछले सालों में कई केस आए जहां लोग घर में मर गए

ऐप की शुरुआत: एक साधारण विचार जो वायरल हो गया

और दिनों तक किसी को पता नहीं चला। यह समस्या युवाओं में भी है, जो काम के दबाव में दोस्तों से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हैं कि वे कितने अकेले महसूस करते हैं, भले ही शहर की भीड़ में रहें। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, और कम्युनिटी सेंटर्स बना रही है, लेकिन समस्या कम नहीं हो रही। आर्थिक विकास ने लोगों को अमीर बनाया, लेकिन रिश्ते कमजोर कर दिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोविड-19 के बाद यह समस्या और बढ़ी, क्योंकि लोग घरों में बंद रहकर अलग-थलग हो गए। अब, 'आर यू डेड?' जैसे ऐप्स इस अकेलेपन को हाइलाइट कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि समाज की चेतावनी है। अगर यह समस्या जारी रही, तो मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, जैसे डिप्रेशन और चिंता। चीन में पहले से ही युवाओं में 'लाइंग फ्लैट' मूवमेंट चल रहा है, जहां लोग काम के दबाव से थककर अलग रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर, 142 करोड़ की आबादी में अकेलापन दिखाता है कि संख्या से ज्यादा रिश्तों की जरूरत है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास की दौड़ में हम इंसानी कनेक्शन खो रहे हैं।

ऐप से छिड़ी बहस: अच्छे और बुरे पहलू

'आर यू डेड?' ऐप की लोकप्रियता ने चीन में एक जोरदार बहस शुरू कर दी है, जहां लोग इसके फायदे और नुकसान पर बात कर रहे हैं। एक तरफ, कई लोग इसे एक अच्छा सेफ्टी टूल मानते हैं, क्योंकि यह अकेले रहने वालों को सुरक्षा देता है। यूजर्स कहते हैं कि अगर कुछ हो जाए, तो कम से कम परिवार को पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शेयर किया कि यह ऐप उन्हें शांति देता है, खासकर उन युवाओं को जो दूर शहरों में काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, ऐप का नाम 'क्या तुम मर गए?' बहुत डरावना लगता है, और कई लोग कहते हैं कि यह मौत की याद दिलाकर नेगेटिव सोच बढ़ाता है। वीबो पर एक यूजर ने लिखा कि इस ऐप की सफलता के पीछे गहरा अकेलापन छिपा है, जो समाज की असफलता दिखाता है। बहस में यह भी आया कि क्या टेक्नोलॉजी असली रिश्तों की जगह ले सकती है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐप समस्या का हल नहीं, बल्कि सिर्फ लक्षण है। अगर लोग ऐप पर निर्भर हो गए, तो असली कनेक्शन और कम हो जाएंगे। इसके अलावा, प्राइवेसी की चिंता भी है, क्योंकि ऐप लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐप वायरल होने के बाद कॉपी ऐप्स आए, जो फ्री हैं लेकिन कम सुरक्षित। सरकार भी इस पर नजर रख रही है, क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों को उजागर कर रहा है। कुल मिलाकर, बहस बैलेंस्ड है: कुछ इसे इनोवेटिव कहते हैं, तो कुछ इसे दुखद। यह दिखाता है कि चीन जैसे देश में, जहां आबादी बड़ी है, लेकिन रिश्ते कमजोर, ऐसी ऐप्स जरूरी हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ऐप्स से अकेलेपन का हल ढूंढ सकते हैं, या हमें समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। यह बहस हमें विचार करने पर मजबूर करती है कि टेक कितनी मददगार है।

समाज पर असर: टेक्नोलॉजी और नीतियों की भूमिका

इस ऐप ने चीन के समाज पर गहरा असर डाला है, और दिखाया है कि टेक्नोलॉजी कैसे सामाजिक समस्याओं से निपट सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप की सफलता ने सरकार को अकेलेपन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। चीन में पहले से ही बुजुर्गों के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अब युवाओं के लिए भी नए कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शहरों में अकेले रहने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू हो रही हैं।

टेक्नोलॉजी कंपनियां भी अब ऐसे ऐप्स बना रही हैं जो सिर्फ सेफ्टी नहीं, बल्कि चैटिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट देती हैं। लेकिन असर सिर्फ पॉजिटिव नहीं है; कुछ लोग कहते हैं कि ऐप मौत की बात करके डर पैदा करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक रूप से, यह ऐप छोटे डेवलपर्स के लिए प्रेरणा है, और दिखाता है कि साधारण आइडिया भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। समाज में, यह ऐप परिवारों को याद दिलाता है कि दूर रहने वाले सदस्यों से संपर्क रखें। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐप वायरल होने के बाद कई लोग अपने रिश्तेदारों से ज्यादा बात करने लगे। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यह अस्थायी है? विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में, सरकार को पॉलिसी बदलनी होगी, जैसे फैमिली सपोर्ट बढ़ाना और काम के घंटे कम करना। 142 करोड़ की आबादी में, अगर अकेलापन बढ़ा, तो उत्पादकता पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह ऐप एक वेक-अप कॉल है, जो टेक और समाज के बीच बैलेंस की जरूरत बताता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां ऐप्स इंसानों की जगह ले लें।

आगे की राह: अकेलेपन से लड़ने के तरीके

'आर यू डेड?' ऐप की कहानी हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां अकेलापन और बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 तक चीन में अकेले रहने वालों की संख्या 100 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में, ऐप जैसे टूल्स मददगार होंगे, लेकिन असली हल समाज में बदलाव है। सरकार को फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे छुट्टियां बढ़ाना और कम्युनिटी इवेंट्स। युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जरूरी हैं, जहां वे अपनी परेशानियां शेयर कर सकें। टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ सकती है, जैसे एआई चैटबॉट्स जो दोस्त की तरह बात करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रिश्तों को भूल रहे हैं? बहस से निकला है कि लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, और परिवार से संपर्क बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर भी यह समस्या है, तो चीन का उदाहरण दुनिया के लिए सबक है। कुल मिलाकर, 142 करोड़ की आबादी में अकेलापन दिखाता है कि हमें संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। यह ऐप एक शुरुआत है, लेकिन रास्ता लंबा है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ऐप्स हमें जिंदा होने की याद दिलाएं, या जहां रिश्ते हमें मजबूत रखें।

सुप्रीम कोर्ट की अपील: POCSO में 'रोमियो-जूलियट' अपवाद क्यों जरूरी?

POCSO कानून की सच्चाई: बच्चों की सुरक्षा या युवा प्यार पर सवाल

भारत का POCSO कानून 2012 में बना था ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके। इस कानून के तहत किसी भी नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है, चाहे वह सहमति से हो या नहीं। लेकिन हाल के सालों में यह कानून कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, खासकर उन मामलों में जहां किशोर लड़के-लड़कियां आपसी प्यार में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को एक फैसले में सरकार से कहा कि POCSO में 'रोमियो-जूलियट' अपवाद डालने पर विचार करे। यह अपवाद उन युवा जोड़ों को बचाएगा जो उम्र में करीब हैं और आपसी सहमति से रिश्ते में हैं। कोर्ट ने देखा कि परिवार वाले अक्सर लड़की के प्यार को रोकने के लिए लड़के पर POCSO का केस कर देते हैं, जिससे युवा लड़के जेल में सड़ते हैं। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अनुरुद्ध मामले में आया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उम्र तय करने के नियमों पर जोर दिया। जस्टिस संजय करोल ने फैसले के आखिर में लिखा कि POCSO का दुरुपयोग समाज में गहरी खाई पैदा कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि असली शोषण के मामलों में बच्चे डर, गरीबी या बदनामी से चुप रहते हैं, जबकि अमीर या प्रभावशाली लोग कानून का फायदा उठाकर बदला लेते हैं। कई हाई कोर्ट पहले भी कह चुके हैं कि POCSO का मकसद बच्चों की रक्षा है, न कि युवा प्यार को अपराध बनाना। लेकिन कानून सख्त होने से कई निर्दोष युवा फंस जाते हैं। यह अपवाद डालने से कानून की मर्यादा बनी रहेगी और न्याय की भावना मजबूत होगी। कोर्ट ने कानून मंत्रालय के सचिव को फैसला भेजा ताकि दुरुपयोग रोकने के कदम उठाए जाएं। यह बात सोचने वाली है कि क्या कानून बच्चों की सुरक्षा करता है या अनजाने में युवा जीवन बर्बाद कर रहा है। समाज को भी सोचना चाहिए कि किशोर उम्र में प्यार स्वाभाविक है, लेकिन शोषण से बचाव जरूरी।

'रोमियो-जूलियट' अपवाद क्या है: प्यार को अपराध से अलग करने का तरीका

'रोमियो-जूलियट' अपवाद का नाम शेक्सपियर की मशहूर कहानी से आया है, जहां दो युवा प्रेमी परिवार की दुश्मनी के बीच प्यार करते हैं। यह अपवाद POCSO जैसे कानूनों में एक छूट है, जो उम्र में करीब किशोरों के बीच सहमति वाले यौन संबंधों को अपराध नहीं मानता। आमतौर पर, अगर दोनों की उम्र में 2 से 5 साल का फर्क हो और दोनों सहमत हों, तो केस नहीं बनेगा। अमेरिका में यह कानून सबसे पहले आया ताकि युवा जोड़ों को वैधानिक बलात्कार के आरोप से बचाया जा सके। कनाडा, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में भी ऐसी व्यवस्था है, जहां सहमति वाले रिश्तों को सुरक्षा मिलती है लेकिन शोषण पर सख्ती बरती जाती है। भारत में POCSO के तहत 18 साल से कम उम्र को बच्चा माना जाता है, इसलिए सहमति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली अपराधी को सजा मिले, न कि प्यार करने वाले युवा फंसें। यह अपवाद डालने से उन मामलों में राहत मिलेगी जहां परिवार रिश्ते को तोड़ने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का प्यार में हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, तो लड़के पर POCSO नहीं लगेगा। लेकिन अगर उम्र का फर्क ज्यादा हो या जबरदस्ती हो, तो कानून लागू रहेगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि POCSO का दुरुपयोग बदला लेने का हथियार बन रहा है। यह अपवाद न्याय को संतुलित बनाएगा, जहां बच्चे सुरक्षित रहें लेकिन युवा आजादी भी मिले। सोचना चाहिए कि क्या हमारा समाज युवा प्यार को समझता है या सिर्फ दंड देता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बदलाव से शिक्षा और जागरूकता बढ़ेगी, न कि सिर्फ सजा से।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता: POCSO का दुरुपयोग और युवा जीवन की बर्बादी

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है, खासकर उन मामलों में जहां परिवार लड़की के प्यार को रोकने के लिए लड़के पर केस कर देते हैं। 9 जनवरी 2026 के फैसले में जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसे केस आम हो गए हैं, जिससे युवा लड़के जेल में बंद रहते हैं। यह बात उत्तर प्रदेश के एक केस से निकली, जहां आरोपी पर POCSO लगा था लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं लगाई लेकिन उम्र तय करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों पर जोर दिया, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट पहले देखें, फिर मेडिकल टेस्ट। कोर्ट ने देखा कि असली शोषण के शिकार बच्चे डर से बोल नहीं पाते, जबकि कुछ लोग कानून से बदला लेते हैं। जस्टिस करोल ने फैसले के अंत में लिखा कि POCSO एक अच्छा कानून है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल न्याय को उल्टा कर देता है। उन्होंने सरकार से अपवाद डालने और दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई का तंत्र बनाने को कहा। कई हाई कोर्ट पहले भी ऐसे केस रद्द कर चुके हैं, जहां रिश्ता सहमति वाला था। उदाहरण के लिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, जहां 14 साल की लड़की के केस में आरोपी बरी हो गया था। कोर्ट ने कहा कि POCSO सहमति नहीं मानता लेकिन युवा रिश्तों को अलग देखना चाहिए। यह अपील सोचने वाली है कि क्या कानून बच्चों की मदद करता है या परिवार की जिद से युवा बर्बाद होते हैं। समाज में किशोर प्यार को समझने की जरूरत है, वरना न्याय की जगह अन्याय बढ़ेगा।

आंकड़े बताते हैं कहानी: POCSO के 24% केस युवा प्यार से जुड़े

एनजीओ एनफोल्ड की स्टडी से पता चला कि असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2016 से 2020 तक के 7064 POCSO केस में से 24.3% 'रोमांटिक' केस थे, जहां लड़की-लड़का आपसी प्यार में थे। इनमें 80.2% केस लड़की के मां-बाप ने कराए, क्योंकि वे रिश्ते के खिलाफ थे। 82% मामलों में लड़की ने आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, जिससे 93.8% केस में आरोपी बरी हो गया। एक दूसरी स्टडी में 264 केस में 25.4% सहमति वाले थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, 2020 में POCSO के तहत 46.7% केस दोस्तों या पार्टनर से जुड़े थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कानून का इस्तेमाल अक्सर परिवार बदला लेने या रिश्ता तोड़ने के लिए करते हैं, खासकर अंतरजाति या अंतरधर्म रिश्तों में। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आंकड़ों पर ध्यान दिया और कहा कि ऐसे केस से न्याय प्रणाली पर बोझ बढ़ता है। लड़कियां घर छोड़कर भागती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, फिर परिवार POCSO लगाता है। लड़के जेल जाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 16-18 साल के किशोर स्वाभाविक रूप से रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कानून उन्हें अपराधी बना देता है। एनफोल्ड स्टडी में 64.9% लड़कियां घर छोड़कर पार्टनर के पास गईं, क्योंकि मां-बाप विरोध करते थे या शादी तय कर देते थे। यह स्थिति सोचने वाली है कि क्या POCSO बच्चों को बचाता है या युवा आजादी छीनता है। सरकार को अपवाद डालकर संतुलन बनाना चाहिए, वरना समाज में विश्वास टूटेगा।

आगे का रास्ता: सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे बने

'रोमियो-जूलियट' अपवाद डालने से POCSO मजबूत होगा, क्योंकि असली शोषण पर फोकस रहेगा और सहमति वाले रिश्तों को छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि दुरुपयोग रोकने का तंत्र बनाए, जैसे गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई। कई देशों में यह काम करता है, जहां उम्र का फर्क कम हो तो अपराध नहीं माना जाता। भारत में सहमति की उम्र 18 है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि 16 साल पर विचार हो, साथ में सेक्स एजुकेशन स्कूलों में शुरू हो। इससे किशोर जागरूक होंगे, शोषण से बचेंगे। लेकिन चुनौती है कि अपवाद से शोषण बढ़ न जाए, इसलिए सख्त जांच जरूरी। समाज को भी बदलना होगा, जहां परिवार प्यार को अपराध मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि न्याय संवेदनशील हो, न कि यांत्रिक। यह अपील विचारोत्तेजक है कि क्या हम युवाओं को समझते हैं या पुरानी सोच से बांधते हैं। सरकार अगर अपवाद डालेगी तो युवा जीवन बचेंगे, न्याय प्रणाली सुधरेगी। लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और प्यार अपराध न बने।

ईरान के विरोध प्रदर्शन: इस बार का अलग रंग और खामेनेई सरकार के सामने चुनौतियां

ईरान में ये नए विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुए, जब तेहरान के बड़े बाजार में दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। वजह थी देश की खराब होती अर्थव्यवस्था – रियाल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई, एक अमेरिकी डॉलर के बदले 1,432,000 रियाल तक पहुंच गई, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। खाने-पीने की चीजों के दाम 70 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए, बिजली और पानी की कमी हो गई, और बेरोजगारी बढ़ती गई। ये प्रदर्शन जल्दी ही पूरे देश में फैल गए, जिसमें छात्र, मजदूर और अलग-अलग जातीय समूह शामिल हो गए। लोग सिर्फ आर्थिक परेशानियों पर नहीं रुके, बल्कि सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, जैसे "तानाशाह की मौत" और "शाह की वापसी"। ये प्रदर्शन 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़े हैं, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। सरकार की गलत नीतियां, जैसे विदेशी गुटों को पैसे देना जबकि घरेलू लोग भूखे हैं, ने आग में घी डाल दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों ने भी अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया। पहले के प्रदर्शनों से अलग, ये बाजार के उन दुकानदारों से शुरू हुए जो हमेशा सरकार के साथ खड़े रहते थे। अब लोग रेजा पहलवी जैसे पुराने राजपरिवार के सदस्य की वापसी की बात कर रहे हैं, जो निर्वासन में रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद का वादा किया और हमलों की धमकी दी। ईरान की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे खबरें बाहर आने में मुश्किल हो गई। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक, हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या पता नहीं चल पा रही। ये स्थिति दिखाती है कि लोग अब सुधार नहीं, बल्कि बड़ा बदलाव चाहते हैं। क्या ये आर्थिक संकट सरकार के लिए अंत की शुरुआत है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले की तरह ये प्रदर्शन जल्दी थमने वाले नहीं लगते। कुल मिलाकर, ये विरोध ईरान की जनता की सालों की कुंठा का नतीजा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है।

पहले प्रदर्शनों से कितने अलग हैं ये

पिछले प्रदर्शनों से ये विरोध काफी अलग हैं, जैसे 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए, जो मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और हिजाब पर केंद्रित थे। उस समय नारा था "महिला, जीवन, आजादी", लेकिन अब नारे सीधे सरकार के खिलाफ हैं, जैसे "तानाशाह को मौत" और "रेजा शाह की वापसी"। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट से शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही राजनैतिक हो गए, जहां लोग पूरे इस्लामिक गणराज्य को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। पहले के विरोध बड़े शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब पूरे 31 प्रांतों में फैले हैं, छोटे शहरों और गांवों तक। बड़ा फर्क ये है कि ये बाजार के व्यापारियों से शुरू हुए, जो पहले सरकार के समर्थक माने जाते थे। अब हड़तालें बड़े स्तर पर हो रही हैं, जैसे कुर्द इलाकों में, जो 1979 की क्रांति की याद दिलाती हैं। सरकार भी कमजोर हो गई है – जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग में कई बड़े नेता मारे गए, अमेरिका ने परमाणु साइटों पर बम गिराए, और सीरिया में असद सरकार गिर गई, जिससे ईरान के सहयोगी कम हो गए। हीजबुल्लाह जैसे गुट भी कमजोर पड़े हैं। लोग अब विदेशी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे "न गाजा, न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए"। सर्वे बताते हैं कि लोग अब चुनाव या सुधारों से नहीं, बल्कि विरोध और बाहरी दबाव से बदलाव चाहते हैं। ट्रंप की धमकियां, जैसे अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो हमला करेंगे, ने माहौल बदल दिया है। पहले के विरोध में महिलाएं और युवा मुख्य थे, लेकिन अब सभी वर्ग शामिल हैं, यहां तक कि पुरुष युवा और जातीय अल्पसंख्यक। हिजाब जैसे नियमों को लागू करने की ताकत भी सरकार के पास नहीं बची। क्या ये फर्क सरकार को गिरा सकता है? ये विचारणीय है, क्योंकि जनता अब थक चुकी है और बड़ा बदलाव मांग रही है। कुल में, ये प्रदर्शन पहले से ज्यादा एकजुट और गहरे हैं, जो शासन की जड़ों को हिला रहे हैं।

सरकार की सख्त कार्रवाई और चुनौतियां

खामेनेई सरकार ने इन प्रदर्शनों पर सख्त रुख अपनाया है, जैसे 8 जनवरी 2026 से पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को हर घंटे 1.56 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। सुरक्षा बलों, जैसे आईआरजीसी और बसिज, ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हजारों मारे गए – सरकारी आंकड़े 2,000 से 3,000 कहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता 12,000 से 20,000 तक बताते हैं। गिरफ्तारियां 19,000 से ज्यादा हो चुकी हैं, और परिवारों को शव नहीं दिए जा रहे, बल्कि झूठी कहानियां कहने को मजबूर किया जा रहा है। अस्पतालों पर छापे मारे गए, जहां घायलों को गिरफ्तार किया या इंजेक्शन देकर मारा। विदेशी मिलिशिया, जैसे इराकी शिया गुट, को बुलाया गया दमन के लिए। खामेनेई ने खुद आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओ, और उन्हें "अमेरिकी एजेंट" या "बागी" कहा। जबरन कबूलनामे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया, और रात के प्रदर्शन रोकने के लिए टैंक तक उतारे गए। लेकिन ये कार्रवाई सरकार की कमजोरी दिखाती है – सेना की तैनाती लंबे समय तक नहीं चल सकती, और आर्थिक संकट और गहरा हो रहा है। नेताओं ने अपने पैसे विदेश भेज दिए, जैसे 1.5 बिलियन डॉलर, जो बैंकिंग सिस्टम पर भरोसे की कमी दिखाता है। चुनौतियां बड़ी हैं – क्षेत्रीय सहयोगी कमजोर, जैसे हिजबुल्लाह और असद सरकार का गिरना। क्या ये दमन लंबा चलेगा? ये सोचने लायक है, क्योंकि जनता की नाराजगी बढ़ रही है, और बाहरी दबाव, जैसे अमेरिका की धमकियां, सरकार को अलग-थलग कर रहे हैं। कुल मिलाकर, ये कार्रवाई तात्कालिक है, लेकिन लंबे समय में समस्या हल नहीं कर रही।

खामेनेई सरकार के पास क्या विकल्प हैं

खामेनेई सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, क्योंकि वो अलग-थलग हो गई है। एक रास्ता है आर्थिक सुधार, जैसे सेंट्रल बैंक गवर्नर बदलना या 7 डॉलर महीने की नकद मदद देना, लेकिन ये छोटे कदम हैं और महंगाई या मुद्रा संकट हल नहीं कर रहे। लोग अब परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, जो संकट बढ़ा रहा है – सरकार अमेरिका से बातचीत कर सकती है संकटों को हटाने के लिए, लेकिन खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं। दमन जारी रखना एक विकल्प है, लेकिन ये महंगा और थकाने वाला है – सुरक्षा बलों की तैनाती लंबी नहीं चलेगी। बातचीत की पेशकश की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को "उपद्रवी" कहकर विश्वास नहीं जीता जा रहा। विदेशी दबाव बढ़ रहा है, जैसे ट्रंप की सैन्य हस्तक्षेप की धमकी, जिससे सरकार वेनेजुएला जैसी डील सोच सकती है, जहां नेतृत्व बदले लेकिन सिस्टम बचे। लेकिन सर्वे बताते हैं कि लोग अब प्रदर्शन और बाहरी मदद से बदलाव चाहते हैं, न कि सुधारों से। नेताओं ने पैसे दुबई जैसे जगहों पर भेज दिए, जो सरकार की अनिश्चितता दिखाता है – खामेनेई के बेटे ने 328 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए। क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये विचार करने योग्य है, क्योंकि बिना आर्थिक बदलाव के विरोध फिर शुरू हो सकते हैं। कुल में, सरकार के विकल्प कम हैं – या तो दबाव झेलो या बातचीत से रास्ता निकालो, लेकिन अलगाव बढ़ रहा है।

आगे की संभावनाएं और विचार

ये प्रदर्शन थम गए लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अस्थायी है – आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, जैसे महंगाई और बेरोजगारी, जो फिर विरोध भड़का सकती हैं। सरकार सुधार नहीं कर रही, जिससे जनता की नाराजगी बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका और यूरोपीय संघ दबाव डाल रहे हैं, जैसे प्रतिबंध और नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह। ट्रंप की "मदद आने वाली है" वाली बात ने उम्मीद जगाई है, लेकिन युद्ध की आशंका भी है। क्या शासन गिरेगा? सर्वे दिखाते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस पर सहमति नहीं। कुछ रेजा पहलवी जैसे संक्रमणकालीन सरकार चाहते हैं, लेकिन एकता की कमी है। ईरान की जनता अब थक चुकी है, और ये विरोध दिखाते हैं कि पुरानी व्यवस्था चल नहीं सकती। क्या शांतिपूर्ण बदलाव संभव है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंसा बढ़ रही है। कुल मिलाकर, आगे अस्थिरता लगती है, लेकिन ये ईरान के लोगों के हाथ में है कि वो किस दिशा में जाते हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

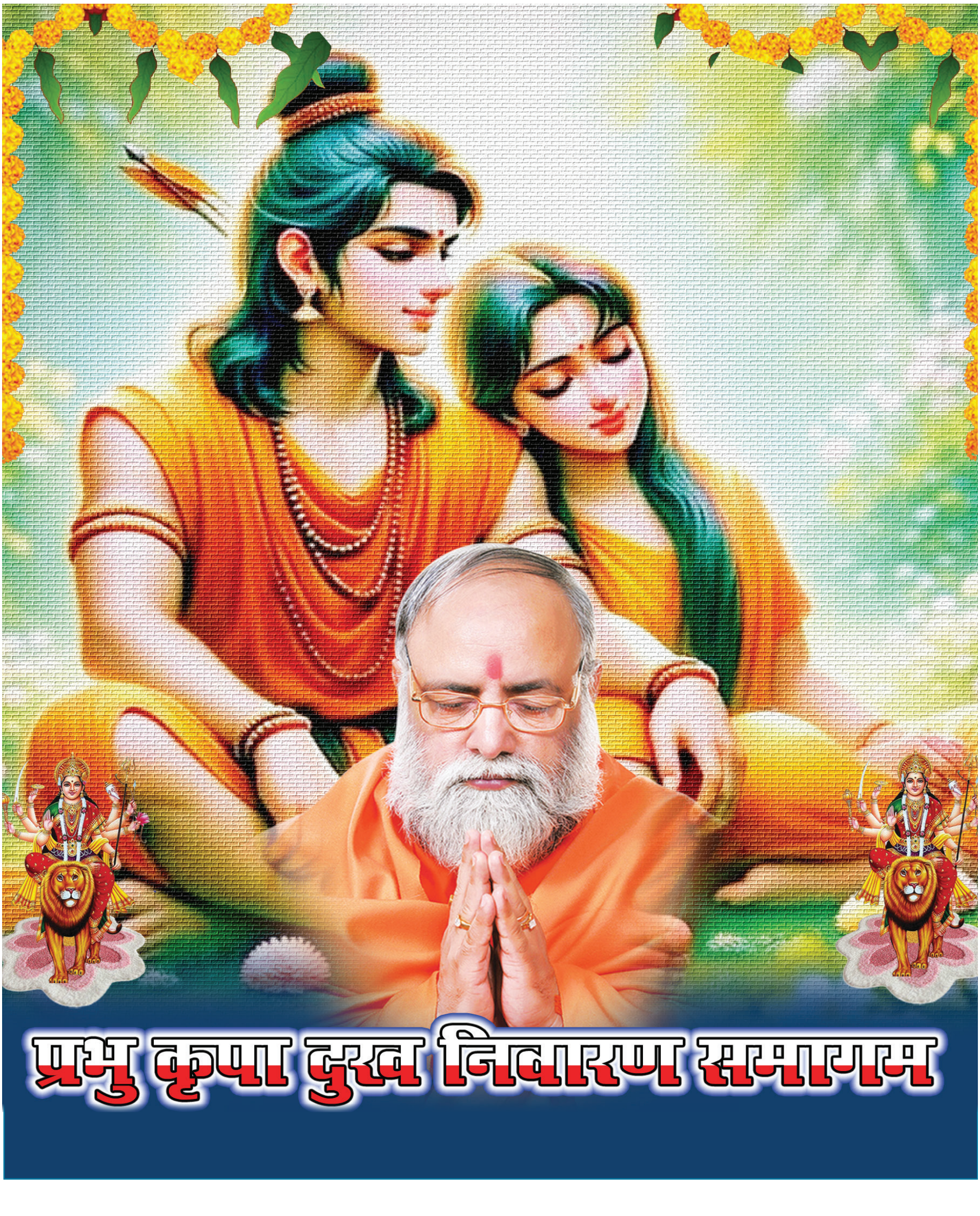

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries